



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 मार्गशीर्ष, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

*Shimla, the 2nd December, 2021*

**No. HHC/Estt.3(1052)/2020.**—19 days earned leave on and with effect from 20-12-2021 to 7-01-2022 with permission to prefix Sunday fell on 19-12-2021 and suffix Second Saturday and

Sunday fell on 8-01-2022 and 9-01-2022, is hereby sanctioned in favour of Smt. Sheela Sood, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Sheela Sood has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sheela Sood would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 7th December, 2021*

**No. HHC/Admn.3(177)/82-I.**—14 days earned leave on and with effect from 18-12-2021 to 31-12-2021 is hereby sanctioned in favour of Shri Suresh Kumar, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Suresh Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Suresh Kumar would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 1st December, 2021*

**No. HHC/Admn.3(390)/94-I.**—10 days earned leave with effect from 01-12-2021 to 10-12-2021, with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 11-12-2021 and 12-12-2021, is hereby sanctioned, in favour of Shri Rajesh Kumar Sharma, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 2nd December, 2021*

**No. HHC/Admn.3(253)/87-I.**—12 days earned leave on and w.e.f. 13-12-2021 to 24-12-2021 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 11th & 12th December, 2021 and suffix Gazetted holiday and Sunday falling on 25th & 26th December, 2021 is hereby sanctioned in favour of Shri Sanam Ram Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Sanam Ram Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Sanam Ram Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 1st December, 2021*

**No. HHC/Admn.3(246)/86-I.**—15 days earned leave on and with effect from 13-12-2021 to 27-12-2021, with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 11-12-2021 and 12-12-2021, is hereby sanctioned, in favour of Shri Parmod Kumar Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Parmod Kumar Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Parmod Kumar Chauhan would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001****NOTIFICATION***Shimla, the 2nd December, 2021*

**No. HHC/Admn.3(383)/93-II.**—09 days earned leave on and with effect from 13-12-2021 to 21-12-2021, with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 11-12-2021 and 12-12-2021, is hereby sanctioned in favour of Ms. Bimla Verma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Ms. Bimla Verma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Ms. Bimla Verma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for her proceeding on leave.

By order,  
Sd/-  
Registrar General.

सामान्य प्रशासन विभाग  
(गोपनीय और मन्त्रिमण्डल)

अधिसूचना

शिमला-2, 10 दिसम्बर, 2021

**संख्या: जी.ए.डी.-सी.-ए(3)2/2019.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्य संचालन (आबंटन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. कार्य संचालन का आबंटन.**—(1) हिमाचल प्रदेश सरकार का समस्त कार्य संचालन अनुसूची 'क' और 'ख' में यथा विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश के विभागों में संव्यवहृत किया जाएगा और उन विभागों में उसे इस प्रकार वर्गीकृत और वितरित किया जाएगा जैसा उनमें अधिकथित किया गया है।

(2) प्रत्येक विभाग के लिए एक सचिव होगा जो विभाग का शासकीय प्रमुख होगा:

परन्तु यह कि —

(1) एक से अधिक विभागों का प्रभार एक ही सचिव को दिया जा सकेगा;

(2) विभाग के कार्य को दो या दो से अधिक सचिवों को बांटा जा सकेगा।

**3. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—**(1) अधिसूचना संख्या: 5-2/71-जी.ए.डी.(सी.सी.), तारीख 25 जनवरी, 1971 द्वारा अधिसूचित दी बिजनस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (एलोकेशन) रूल्ज़, 1971 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

राज्यपाल के आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,  
मुख्य सचिव।

### अनुसूची-अ

#### विभागों की सूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम
1.	कृषि विभाग
2.	पशुपालन विभाग
3.	आयुष विभाग
4.	सहकारिता विभाग
5.	निर्वाचन विभाग
6.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
7.	पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
8.	राज्य कर एवं आबकारी विभाग
9.	वित्त विभाग
	(क) वित्त
	(ख) हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग
	(ग) कोषागार, लेखा एवं लॉटरीज़
10.	मत्स्य विभाग
11.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
12.	वन विभाग
13.	सामान्य प्रशासन विभाग
	(क) सामान्य, राजनैतिक एवं विविध
	(ख) गोपनीय एवं मन्त्रिमण्डल
	(ग) आतिथ्य एवं सत्कार
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
15.	उच्चतर शिक्षा विभाग
16.	गृह विभाग
	(क) गृह
	(ख) सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध
	(ग) न्यायालयिक सेवाएं निदेशालय
17.	उद्यान विभाग
18.	आवास विभाग
19.	उद्योग विभाग
20.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

21. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
22. जल शक्ति विभाग
23. श्रम एवं रोज़गार विभाग
  - (क) श्रम
  - (ख) रोज़गार
24. भाषा एवं संस्कृति विभाग
25. विधि एवं विधि परामर्शी विभाग
26. चिकित्सा शिक्षा विभाग
27. बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग
28. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग
29. पंचायती राज विभाग
30. संसदीय मामले विभाग
31. कार्मिक विभाग
  - (क) नियुक्ति
  - (ख) सचिवालय प्रशासन
  - (ग) प्रशासनिक सुधार
  - (घ) प्रशिक्षण
  - (ङ) प्रशासनिक योजना एवं मूल्यांकन
32. योजना विभाग
  - (क) योजना
  - (ख) अर्थ एवं सांख्यिकी
  - (ग) बीस-सूत्रीय कार्यक्रम
33. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
34. लोक निर्माण विभाग
35. लोक शिकायत निवारण विभाग
36. राजस्व विभाग
  - (क) भू-राजस्व
  - (ख) भू-अभिलेख
  - (ग) जिला गज़ेटियर
  - (घ) भू-एकत्रीकरण
  - (ङ) उपनिवेशन
  - (च) राहत, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन
  - (छ) भू-सुधार
  - (ज) प्राकृतिक आपदा
37. ग्रामीण विकास विभाग
38. सैनिक कल्याण विभाग
39. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  - (क) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
  - (ख) महिला एवं बाल विकास
40. तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
41. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
42. नगर एवं ग्राम योजना विभाग
43. परिवहन विभाग
44. जनजातीय विकास विभाग
45. शहरी विकास विभाग
46. युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

## अनुसूची-आ

## 1. कृषि विभाग

1. कृषि अधिनियमों का प्रशासन
2. कृषि उपज एवं विस्तार
3. कृषि प्रशिक्षण, वृत्तिकाएं एवं छात्रवृत्तियां
4. फसलों का पौध संरक्षण
5. कृषि ऋण एवं अग्रिम
6. बीज कृषि क्षेत्र (बीज फार्म) एवं बीज प्रमाणन
7. मृदा परीक्षण, मृदा सर्वेक्षण एवं भू-उपयोग
8. अधिक अन्न उगाओ अभियान
9. कृषि सूचना सेवा
10. गहन कृषि परियोजनाएं
11. कृषि उपकरणों एवं ट्रैक्टरों का आबंटन
12. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर
13. लघु किसानों / सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित मामले
14. कृषि के लिए बंजर भूमि का उद्धार
15. लघु सिंचाई
16. कृषि वित्त पोषण
17. ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र
18. स्थापना, बजट एवं लेखा मामले
19. कृषि भूमि पर मृदा संरक्षण
20. चाय विकास, प्रसंस्करण एवं विपणन
21. कॉफी की खेती एवं विकास

## 2. पशुपालन विभाग

1. विभाग से सम्बन्धित अधिनियमों का प्रशासन
2. पशुपालन कार्यक्रम एवं विस्तार कार्य
3. पशु चिकित्सा सहायता एवं सेवाएं-अस्पताल, औषधालय, दूरस्थ औषधालय जिसके अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र भी हैं।
4. मवेशी, भेड़ और बकरियों, घोड़ों, खच्चरों, कुक्कट (मुर्गी) पालन, सुअर पालन आदि के विकास से सम्बन्धित स्कीमें।
5. रोग जांच स्कीमें
6. दुग्ध उत्पादन (विकास) एवं गोसदनों और गोशालाओं का विकास
7. प्रमुख ग्राम स्कीमें
8. दुग्ध आपूर्ति स्कीमें
9. पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन प्रशिक्षण
10. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
11. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ऊन संघ और उनकी घटक सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 की धारा 35, 94 और 100 का प्रशासन।

## 3. आयुष विभाग

1. आई.एस.एम. फार्मसियों / केंद्रीय सहायता का विकास
2. आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित सम्मेलन
3. हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला से सम्बन्धित मामले
4. होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी बोर्ड अधिनियम और नियम

5. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पतालों, जिला आयुर्वेदिक अस्पतालों, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधालयों का प्रशासन और उनका संचालन।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भागीदारी
7. आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति, हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक फार्मेशियों और अनुसंधान केन्द्रों के प्रबंधन और उनके संचालन के बोर्ड से सम्बन्धित समस्त मामले।
8. आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा और प्रशिक्षण
9. स्थापन, बजट एवं लेखा

#### 4. सहकारिता विभाग

1. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी ऊन संघ एवं उनके संघटक सहकारी समिति संस्थानों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1968 की धारा 35, 94 और 100 के प्रशासन के सिवाय सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त प्रकार और समस्त स्तरों की सहकारी सोसाइटियों से सम्बन्धित सभी कार्य।
2. शहरी सहकारी बैं
3. भूमि बन्धक बैंक
4. सोसाइटियों को ऋण एवं सहायकियाँ प्रदान करना
5. सोसाइटियों की शेयर पूंजी में निवेश
6. फसल ऋण स्कीमें
7. कृषि उपज का विपणन
8. सहकारिता के माध्यम से उर्वरकों, बीजों और अन्य कृषि निवेशों का वितरण
9. सहकारी प्रसंस्करण और गोदाम गतिविधियाँ
10. सहकारी विधि, अधिनियम और नियम
11. सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा
12. उपभोक्ता सहकारी भंडार
13. परिसमापन, मध्यस्थता और पुरस्कारों का निष्पादन
14. मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋणों की विशेष स्कीमें।
15. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण
16. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले

#### 5. निर्वाचन विभाग

1. संसद के लिए निर्वाचन
2. राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचन
3. निर्वाचन आयोग से और को निर्देश
4. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले

#### 6. प्रारंभिक शिक्षा विभाग

1. प्रारंभिक शिक्षा अर्थात् कक्षा – प्रथम से आठवीं तक की शिक्षा
2. शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रारम्भिक स्तर तक प्रशिक्षण संस्थान
3. प्रारम्भिक शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान सहायता।
4. प्रारंभिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ
5. पाठ्य-पुस्तकें
6. प्रारम्भिक शिक्षा में क्रीड़ा (खेल-कूद)
7. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
8. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग और सहबद्ध मामले
9. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त अन्य मामले/कार्यक्रम/क्रियाकलाप
10. प्रौढ़ शिक्षा स्कीम/साक्षरता स्कीम (अनौपचारिक शिक्षा)



11. शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राज्य परिषद
12. विद्यालय पुस्तकालय
13. बालबाड़ी (नर्सरी) विद्यालय

## 7. पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

### (अ) पर्यावरण और प्रदूषण नियन्त्रण

(क) पर्यावरण और प्रदूषण के नियन्त्रण के संरक्षण से सम्बन्धित समस्त अधिनियमों और नियमों के अधीन निहित समस्त शक्तियों का प्रयोग करना। राज्य सरकार की ओर से समस्त पर्यावरण विधानों का कार्यान्वयन/प्रवर्तन, जिसे राज्य बोर्ड या किसी अन्य अभिकरण द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है:

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकरण अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (नीचे सूचीबद्ध नियम)
5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हैंडलिंग) नियम, 1998
6. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन और हैंडलिंग) नियम, 1989
7. खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
8. खतरनाक सूक्ष्म जीवों/आनुवांशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, और भंडारण नियम, 1989।
9. पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999
10. ओजोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियन्त्रण) नियम, 2000
11. बैटरी (प्रबन्धन और हैंडलिंग) नियम, 2001
12. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियन्त्रण) नियम, 2000
13. नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हैंडलिंग) नियम, 2000
14. पर्यावरणीय मंजूरी के लिए नोडल एजेंसी

### (ख) पर्यावरण और प्रदूषण नियन्त्रण के अधीन अन्य कृत्य निम्नानुसार हैं:

1. विशिष्टतः राज्य संसाधनों स्रोतों पर और सामान्यतः हिमालयी क्षेत्रों पर "पर्यावरणीय सूची" का संग्रहण करना, तैयार करना और उसका प्रसार करना।
2. जनसाधारण के बीच पर्यावरणीय जागरूकता, प्रशिक्षण और पर्यावरण और प्रदूषण नियन्त्रण पर अनुसंधान से सम्बन्धित समस्त मामलों पर विचार करना।
3. पर्यावरण पर परियोजनाओं के विकास के समाघात को मॉनीटर करना और उसका निर्धारण करना
4. पर्यावरणीय अनुरूप भू उपयोग और पारिस्थितिकी विनिर्दिष्ट परिवर्तन और समस्त संसाधनों का धारणीय उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरणीय योजना के माध्यम से विकास प्रक्रिया में पर्यावरणीय समुत्थानों को जोड़ना।
5. पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण के साथ-साथ पर्यावरण के क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से मुख्य संस्थानों के साथ सहयोग से शोध और विकास करना।
6. परिसंकटमय रसायनों और अपशिष्ट के स्रोत का आविष्करण, उपचार प्रौद्योगिकियों पर डेटाबेस का सृजन और सम्बद्ध के लिए परामर्शदात्री व्यवस्था करना।
7. राज्य में कृषि और उद्यान क्रियाकलापों के सम्भाव्य समाघातों का अध्ययन करना और "प्रदूषण के गैर-बिन्दु संसाधनों" जैसे रासायनिक उर्वरकों, नाशकजीवमार कीटनाशी और मिट्टी और जल संसाधनों, पर अन्य रसायनों का वनस्पतियों, प्राणिजात और समुदायों पर अध्ययन करना और इस बाबत न्यूनीकरण उपाय/विकल्प सुझाना
8. पर्यावरणीय विषयों पर सरकार को परामर्श देना
9. पर्यावरण समाघात अवधारण के मामलों की जांच करना और भारत सरकार को इसकी अनुशंसा करना।

10. ई आई ए तंत्र के अधीन एस ई आई ए और एम सी, एस ई आई ए ए और एस ई ए सी का संपूर्ण नियंत्रण।
11. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण प्रबंधन योजना के पर्यावरणीय समाघात अवधारण और अनुश्रवण में अन्तर्विष्ट वैधता और तथ्यों पर विचार करना।
12. राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावकों को पर्यावरण मंजूरी के समय भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग।
13. विभिन्न उद्योगों/प्रस्तावकों द्वारा अंगीकृत प्रदूषण नियंत्रण उपायों/उपकरणों की मानीटरिंग करना
14. प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से संबंधित सभी मामले और न्यूनीकरण/उपचारात्मक कार्य योजना कार्यक्रम सुझाव देना।
15. स्थल पर और स्थल से बाहर आपातकालीन योजना और सार्वजनिक उत्तरदायी बीमा कवर आदि जैसी लिखत के माध्यम से संभावित औद्योगिक दुर्घटनाओं और न्यूनीकरण से संबंधित आपदा प्रबंधन पर डेटा बैंक बनाना।
16. राज्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, के मध्य समन्वय करना जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण में अन्तर्वलित हैं।
17. जैव-विविधता, जीवमंडल, प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनीकरण और प्रबंधन, आर्द्रभूमि, घास-भूमियों आदि का संरक्षण और संरक्षण से संबंधित समस्त मामलों पर विचार करना।
18. समस्त पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यक्रमों पर विचार करना और परियोजना प्रस्तावकों और विनियामकों द्वारा पर्यावरण मॉनिटरिंग और प्रबंधन सूचना के अगलक्षी प्रकटीकरण को बढ़ावा देना।
19. उपरोक्त नियमों और विनियमों और अधिनियमों के संबंध में पर्यावरणीय मुकद्दमेबाजी से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना।
20. राज्य में विभिन्न प्रदूषकों के संबंध में पर्यावरणीय मानकों की विरचना/अनुरक्षण
21. प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन
22. पर्यावरणीय योजना से संबंधित मामले

### (आ) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. हिमाचल प्रदेश राज्य से सुसंगत किसी भी क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का विकास/उपान्तरण/अंगीकार करना।
2. राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं में वैज्ञानिक हस्तक्षेप में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकियों का प्रसार और प्रचार करना।
3. आधुनिक तकनीकों के उपयोग से नए डेटाबेस का सृजन करना
4. हिमाचल प्रदेश राज्य में उपयोग के लिए समुचित प्रौद्योगिकियों का विकास करना
5. विकास के वैकल्पिक धारणीय पद्धति को बढ़ावा देने वाले संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मॉडल विकसित करने हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रसार।
6. राज्य में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता और बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना
7. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों के साथ प्रभावी संपर्क विकसित करना
8. राज्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति विकसित करना
9. जैविक प्रदूषण, अनुसंधान और विकास, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, क्षमता अध्ययन, जीवन चक्र, सतत विकास, जैव विविधता और आनुवांशिक रचना जैसे विवादों का समाधान करना।
10. औद्योगिकीय और तकनीकी संयोजन को विकसित करने और स्थापित करने की दिशा में प्रयासों के लिए निर्देश देना।
11. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय जानकारी की दक्ष राज्य-व्यापी प्रणाली स्थापित करना
12. सामाजिक-आर्थिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व को बढ़ावा देना
13. समाज के प्रति विज्ञान की प्रासंगिकता को बढ़ावा देना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेश की भागीदारी में लैंगिक समानता में वृद्धि करना।
14. विश्वविद्यालयों, उद्योग, अनुसंधान और विकास, गैर-सरकारी संगठन और सरकारी क्षेत्र सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के मध्य परामर्श, संपर्क और नेटवर्किंग को प्रोत्साहन देना।

15. विज्ञान लोकप्रियकारी कार्यक्रम के अधीन उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ करना।

### (इ) जैव प्रौद्योगिकी:

1. राज्य में जैव-प्रौद्योगिकी नीति की विरचना और उसका कार्यान्वयन
2. जैव प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन और विद्यमान बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और राज्य में अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के जैव प्रौद्योगिकी और तकनीकी उन्नयन में दक्ष जनशक्ति का सृजन करने हेतु इसमें निरंतर सुधार करना।
3. राज्य में, वन/पशु आनुवांशिक संसाधनों और उत्तक विकास सहित स्थानीय जैव संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रमुखता देते हुए, जैव-प्रौद्योगिकी और जैव-सूचना आधारित कार्यकलापों के लिए उद्यमिता विकास और नियोजन सृजन को प्रोत्साहन देना।
4. जैव-प्रौद्योगिकी में उभरती प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दाताओं से संसाधनों का सृजन करना।
5. प्राइवेट/सार्वजनिक/संयुक्त सेक्टरों में जैव प्रौद्योगिकी प्रारंभिक सुविधाओं की स्थापना करना
6. राज्य में विभिन्न स्थानों पर जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों और जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिक समूहों (क्लस्टरज़) की स्थापना करना।
7. उत्कृष्ट और रोगमुक्त उन्नत जीनोटाइप, प्रोटोकॉल के विकास और वाणिज्यिक उत्पादन हेतु उनके शोधन (औषधीय और सुगंधित जड़ी बूटियों, ऑर्किड और अन्य सजावटी पौधों सहित) के माध्यम से खेती का विविधीकरण।
8. राज्य में जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों में निवेश करने हेतु लघु-उद्यमियों और अन्य औद्योगिक घरानों को आकर्षित करना।
9. राष्ट्रीय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव-प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों के लिए विपणन नेटवर्क का विकास।
10. प्रयोगशाला से उद्योग और मण्डी तक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ निजी निवेशकों/अन्य संगठनों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों (जे.वी.सी.) की स्थापना करना।
11. जैव-प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय को प्रोत्साहन देने हेतु उद्यम पूंजी निधि का सृजन
12. राज्य में जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रसुविधा की स्थापना करना
13. परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक रूप से रचित जीवों, कोशिकाओं या फसलों के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण हेतु नियमों का कार्यान्वयन।

### 8. राज्य कर एवं आबकारी विभाग

1. आबकारी एवं कराधान अधिनियमों और तदधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन
2. माल के विक्रय या क्रय पर कर
3. मनोरंजन, मनोविनोद, बाजी लगाने और जुए पर कर सहित विलास वस्तु-कर
4. व्यवसाय, व्यापार और आजीविका पर कर
5. शहरी अचल सम्पत्तियों पर कर
6. अतिरिक्त माल कर
7. पथकर कर
8. कृषि-उपज सम्बन्धी मामलों पर कर
9. मादक द्रव्य, स्वापक औषधि और अफीम
10. मानवीय उपभोग हेतु मद्यसारिक पान और प्रसाधन निर्मितियों पर उत्पाद-शुल्क
11. प्रतिषेध पॉलिसी
12. स्थापना, बजट एवं लेखा मामले

### 9. वित्त विभाग

#### (क) वित्त

1. राज्य बजट को तैयार करना और उसका संकलन करना
2. अनुपूरक प्राक्कलन और अनुदानों और विनियोगों की अतिरिक्त मांग
3. विनियोग इकाइयों (यूनिट) विहित करना
4. लोक निधियों का प्रबंधन जिसके अन्तर्गत:—
  - (क) अधिशेष रोकड़ का विनिधान
  - (ख) आकस्मिक निधि
  - (ग) प्राप्ति की प्रगति देखना
  - (घ) योजनागत व्यय में भारत सरकार के अंश (शेयर) की वसूली और योजनागत व्यय के लिए स्रोत
  - (ङ) योजनागत व्यय की वसूलियों का निर्धारण
5. व्यय की नई मदों की वित्तीय संवीक्षा
6. व्यय का बजट नियन्त्रण
7. कराधान प्रस्ताव
8. सामान्य वित्तीय प्रशासन जिसके अन्तर्गत:—
  - (क) प्राधिकरण का उस विस्तार तक विनिश्चय करना जहां तक प्राप्तियों और भण्डार स्टॉक खातों की लेखा परीक्षा प्रावर्तित की जानी है;
  - (ख) सरकारी कर्मचारियों के नियमों की विरचना, उनकी सेवा की शर्तें, विनियमित करने सहित उसमें संशोधन करना और छूट देना भी है;
  - (ग) आयकर में राज्य का अंश;
  - (घ) संघ के आबकारी शुल्कों में राज्य का अंश;
  - (ङ) सम्पदा शुल्क में राज्य का अंश; और
  - (च) रेलवे के किरायों पर करों में राज्य के अंश के बदले अनुदान
9. राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले मामलों पर सलाह देना अर्थात:—
  - (क) अनुदान, अभिदायों, प्रतिदायों एवं सेवाएं, आकस्मिकताएं, अन्य सरकारी विभागों आदि को किए गये संदायों (भुगतान) से वसूली, राज्य ऋणों और अग्रिमों और धन से सम्बन्धित विषय साधारणतया आकस्मिकताओं और “प्रतिदायों और सेवाओं” के लिए किए गए अनुदानों से हुए गबन, व्यपहरण और उपगत हानि से सम्बन्धित मामले।
  - (ख) अधिकारियों का यात्रा भत्ता और स्थापना सहित उपलब्धियां, पेंशन, उपदान और भत्ते
  - (ग) ऋण और अग्रिम जैसे कार अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम, मार्ग अग्रिम और सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.फंड) अग्रिम आदि।
  - (घ) खजाना में हुई गबन, व्यपहरण और हानियां
10. समस्त विभागों से सम्बन्धित वित्तीय विवक्षा आदि से अन्तर्वलित संज्ञापन मामले
11. राज्य सरकार द्वारा बाजार से उधार लेना और कानूनी स्वायत्त निकायों द्वारा लिए गए ऋणों पर गारन्टी देना।
12. वित्तीय नियमों की विरचना करना और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करना
13. विद्यमान करों की दरों में वृद्धि या कमी करने और अतिरिक्त स्रोत के दोहन के लिए प्रस्तावों का परीक्षण करना।
14. विदेशी विनिमय
15. कोषागारों एवं उप-कोषागारों पर नियन्त्रण
16. मितव्ययिता उपाय, बचत स्कीमें
17. व्यैक्तिक खाता लेखा
18. राज्य लॉटरी
19. संपरीक्षा रिपोर्ट — महालेखाकार और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक

20. लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टें
21. वेतन का नियतन सहित वेतनमानों का संशोधन
22. राज्य की आय और व्यय पर पर्यवेक्षण
23. लेखापरीक्षा आक्षेपों का निपटान
24. बैंक एवं बैंककारी आयोग से सम्बन्धित समस्त मामले
25. पूर्ववर्ती राज्य के कर्मचारियों के पेंशन मामले
26. राज्य बीमा
27. आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारिवृन्द और दूरभाष
28. हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग।
29. मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को रोजगार सहायता प्रदान करने की नीति विरचित करना। विद्यमान नीति में संशोधन करने से सम्बन्धित समस्त नीति मामलों सहित जब कभी आवश्यक हो निदेश जारी करना और तद्धीन पात्र आश्रितों को रोजगार सहायता उपलब्ध करवाना।

### (ख) हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग

1. निम्नलिखित के लेखों की परीक्षा करना—
  - (क) अधिसूचित क्षेत्र समितियों सहित नगर निगमों/नगरपालिक समितियों
  - (ख) ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों
  - (ग) प्रतिपाल्य अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्ड्स)
  - (घ) वैयक्तिक खाता लेखा
  - (ङ) संरक्षक एवं वार्ड खाता
  - (च) विश्वविद्यालय।
  - (छ) औद्योगिक विद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों जैसे कि छात्र निधि, क्रीड़ा-निधि, रेड क्रॉस निधि, खेल-कूद निधि, विज्ञान निधि की प्राप्ति और निधियां।
  - (ज) नौघाट, अस्पतालों, पशु-चिकित्सालयों सहायता अनुदान, कर आदि
  - (झ) पूर्त-विन्यास एवं न्यास
  - (ञ) वित्त सचिव के अनुरोध पर विविध लेखे
2. स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना
3. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले

### (ग) कोषागार, लेखा एवं लॉटरीज

1. कोषागार
2. उप-कोषागार
3. बिलों, पेंशनों का भुगतान और सरकारी प्राप्तियों का लेखा-जोखा
4. न्यायिक और न्यायिकेतर स्टाम्पों का उपापन और वितरण
5. कोषागार निर्देशिका
6. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
7. लॉटरीज से सम्बन्धित समस्त मामले

### 10. मत्स्य विभाग

1. मत्स्य अधिनियमों का प्रशासन
2. मत्स्य उत्पादन और उनका विपणन
3. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले

### 11. खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

1. आवश्यक वस्तु अधिनियमों, आदेशों और तद्धीन बनाए गए नियम
2. आवश्यक, नियन्त्रित, आंशिक रूप से नियन्त्रित और अन्य वस्तुएं जैसे कि चीनी, नमक, मिट्टी का तेल, सीमेंट आदि — उनका उपापन, नियन्त्रण तथा वितरण।

3. खाद्यान एवं उनके उत्पाद — उपापन और वितरण सहित सम्बद्ध विधिक आदेशों का प्रशासन
4. चावल एवं आटा मिलें
5. सरकारी खाद्यान्न गोदाम
6. उचित मूल्य की दुकानें
7. ईट-भट्टे
8. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
9. बाट और माप
10. हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

## 12. वन विभाग

1. वन अधिनियमों का प्रशासन
2. मुख्य अरण्यपाल (सी.सी.एफ.) और उसके समकक्ष पंक्ति के अधिकारियों के सिवाए भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) के कार्मिकों की तैनाती।
3. वन बंदोबस्त, वनरोपण कार्य योजना, वन संविदाओं, परिरक्षण, अधिकार प्रदान करने आदि सहित सरकारी वनों के साथ साथ प्राइवेट वन से सम्बन्धित समस्त मामले।
4. इमारती लकड़ी और राल सहित मुख्य और लघु वन उपज का विदोहन
5. भूमि उद्धार, परिरक्षण और जल प्रवाह क्षेत्र प्रबन्धन
6. यान्त्रिक लॉगिंग स्कीमें
7. राल एवं तारपीन कारखाने
8. वनों में वनों के बेहतर प्रबन्धन के लिए आवश्यक सड़कों, भवनों, पुलों और जल नहरों का सन्निर्माण।
9. वन्य जीव का प्रबन्धन, परिरक्षण और संरक्षण
10. धौलाधार परियोजना
11. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
12. वन भूमि और अन्य बंजर भूमि पर मृदा संरक्षण
13. पर्यावरणीय पर्यटन (इको टूरिज़्म)

## 13. सामान्य प्रशासन विभाग

### (क) सामान्य, राजनैतिक एवं विविध

1. वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट — से सम्बन्धित अनुदेश
2. भारत सरकार, राज्य सरकारों और विदेश के मध्य पत्राचार की प्रणाली
3. उच्च पदस्थों की मृत्यु पर की जाने वाली कार्रवाई
4. वैवेकिक अनुदान से सम्बन्धित मामले
5. कार्यालयों का समावेदन
6. राष्ट्रगान
7. राष्ट्रीय एकता
8. राष्ट्रीय सुरक्षा नियम
9. प्रमाण एवं प्रशंसा पत्र
10. राष्ट्रीय नेताओं के रूपचित्र
11. कार्यालयों का वर्गीकरण एवं पुनर्वर्गीकरण
12. जिला प्रशासन का पुर्नगठन
13. कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था
14. केन्द्रीय एवं राज्य नागरिक परिषदें
15. सचिवालय में आवास सुविधा, उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के लिए कार्यालय और निवास स्थान सहित आवास सुविधा तथा समस्त पुलित निवास स्थान सुविधा।
16. संपदा कार्यालय एवं सरकारी वास सुविधा का आबंटन

17. राज्यपाल सचिवालय
18. विधान सभा में राज्यपाल का अभिभाषण
19. राज्यत्व से सम्बन्धित और उससे उद्भूत मामले
20. सीमा विवाद से सम्बन्धित मामले
21. 1966 में पंजाब के पुनर्गठन से उद्भूत समस्याओं सहित सेवाओं का एकीकरण और आबंटन तथा आस्तियों और दायित्वों का विभाजन।
22. अन्तरराज्यिक सीमा क्षेत्र का विकास – सम्बन्धित मामले
23. अन्तरराष्ट्रीय सीमा से सम्बन्धित समस्त मामलों सहित अन्तरराष्ट्रीय सीमा (बोर्डर) जिला का विकास
24. भारत-तिब्बत व्यवसाय
25. उत्तरी-जोन परिषद कारबार
26. राज्यपाल सम्मेलन कारबार
27. प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन
28. हिमाचल प्रदेश के साथ परिक्षेत्रों का विलयन
29. राजनैतिक दलों सहित विभिन्न संगठनों की मांगें
30. सचिवालय कर्मचारिवृन्द एवं विभागीय वाहन
31. संसदीय प्रश्न, विधान सभा प्रश्न (एक से अधिक विभाग का प्रभावित करने वाले)
32. राजनीतिक पीड़ितों से सम्बन्धित मामले
33. युद्धोत्तर सेवाएं पुनर्निर्माण निधि
34. शासकों उनकी सम्पत्तियाँ और प्रिवी पर्स
35. भारत सरकार को दी जाने वाली पाक्षिक रिपोर्टें
36. हिमाचल प्रदेश में डाक, तार, टेलीफोन और बेतार सुविधाएं
37. एक से अधिक विभागों को प्रभावित करने वाले मामले
38. हिमाचल प्रदेश हितकारी निधि का प्रशासन
39. राजपत्रित और स्थानीय अवकाश की घोषणा
40. स्वतंत्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, हिमाचल दिवस, शहीदी दिवस, यू0एन0ओ0 दिवस और अन्य धार्मिक दिवस समारोह मनाना।
41. जनगणना
42. विविध कार्य
43. परिधि गृह और सरकार द्वारा समय समय पर ऐसे परिधि गृहों और विश्राम गृहों में आवास का आरक्षण।
44. जिलों और तहसीलों आदि का पुनर्गठन
45. राज्य / जिला स्तर पर समितियों का युक्तिकरण – उनके अनुदेश
46. जिला राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष और अन्य निधियों का संग्रहण और अन्य सम्बद्ध मामले
47. सम्मान और विशिष्टताएं
48. हिमाचल प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड और हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड

#### (ख) गोपनीय और मंत्रिमण्डल

1. गोपनीय मामले
2. मंत्रिमण्डल और उसकी उप-समितियों की बैठकें
3. आबंटन नियम और कार्य संचालन नियम
4. मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, उप-मंत्री, संसदीय सचिव से संबंधित समस्त प्रश्न

#### (ग) आतिथ्य और सत्कार (प्रोटोकॉल)

1. आतिथ्य
2. प्रोटोकॉल मामले
3. राज्य अतिथि
4. स्थापन, बजट और लेखा मामले

**14. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

1. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य अधिनियम और नियम
2. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का गठन एवं स्थापन
3. निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और समकक्ष पंक्ति (रैंक) के अधिकारियों की नियुक्ति के सिवाए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संवर्ग कर्मियों की तैनाती।
4. हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्मिकों की तैनाती सहित समस्त संबंधित मामले
5. चिकित्सा उपस्थिति नियम
6. स्वच्छता सहित लोक स्वास्थ्य
7. परिवार नियोजन, मातृत्व और शिशु (बाल) कल्याण से संबंधित समस्त संदर्भ
8. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा में शिक्षा और प्रशिक्षण।
9. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य प्रशासन जिसके अन्तर्गत अस्पताल, औषधालय, एलोपैथिक और स्वास्थ्य केंद्र आदि भी हैं।
10. औषधि अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियम
11. महामारी, कुष्ठ, टी.बी.वी.डी., मलेरिया, चेचक और ऐसी अन्य बीमारियों पर नियंत्रण
12. टीकाकरण
13. जन्म और मृत्यु का पंजीकरण
14. जन्म मरण के आंकड़े
15. खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मिलावट
16. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए यूनिसेफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों (एजेंसियों) से सहायता।
17. मानसिक रोगों का उपचार करने वाले अस्पतालों में मानसिक रोगियों का प्रवेश
18. चिकित्सा भण्डार डिपुओं से विभिन्न विभागों के अंतर्गत संस्थानों के लिए चिकित्सा मर्दों की आपूर्ति।
19. स्थापन, बजट और लेखा मामले
20. कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम (योजना) का क्रियान्वयन

**15. उच्चतर शिक्षा विभाग**

1. स्कूल (विद्यालय) शिक्षा
2. महाविद्यालय शिक्षा
3. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
4. शिक्षक प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान
5. श्रव्य दृश्य शिक्षा
6. संस्कृत और हिन्दी संस्थान
7. सामाजिक शिक्षा
8. उच्च और उच्चतर शिक्षा के लिए अनुदान सहायता
9. एन.सी.सी. और ए.सी.सी.
10. सामान्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां और ऋण
11. विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यावसायिक दिशा-निर्देश और परामर्श
12. सामुदायिक केंद्र और विज्ञान मंदिर
13. पुस्तकालय
14. पाठ्य पुस्तकें
15. शैक्षणिक संस्थानों में खेल-कूद
16. भौतिक संस्कृति और शिक्षा
17. स्थापन, बजट और लेखा मामले
18. भाषाई अल्पसंख्यक और उनसे सम्बन्धित सहबद्ध मामले
19. नवोदय विद्यालयों से सम्बन्धित पत्राचार
20. केन्द्रीय विद्यालयों से सम्बन्धित पत्राचार
21. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित पत्राचार



## 16. गृह विभाग

## (क) गृह

1. विधि और व्यवस्था
2. पासपोर्ट और वीजा
3. विदेशी मिशन
4. विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण आदि
5. पाकिस्तानी शरणार्थियों का पुनर्वास
6. शस्त्र और गोला-बारूद
7. होमगार्ड (गृह-रक्षक) और नागरिक-सुरक्षा
8. पुलिस विभाग के सदस्यों की ओर से भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री और राज्यपाल को संबोधित अपील, अभ्यावेदन और याचिकाएं।
9. आपातकालीन राहत संगठन
10. हिमाचल सशस्त्र पुलिस सहित पुलिस:-
  - (क) पुलिस प्रशासन
  - (ख) शस्त्र और गोला बारूद
  - (ग) अपील, पुलिस के अभ्यावेदन
  - (घ) सुरक्षा, आसूचना, गुप्तचर्या और काउंटर-गुप्तचर जासूसी
  - (ङ) सीमा-सुरक्षा बल
  - (च) विधि और व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामले
  - (छ) निवारक निरोध अधिनियम के अधीन सलाहकार समिति
11. कैदियों की अपील दया याचिकाएं सुधार आदि
12. माफी (क्षमा) और पैरोल
13. पाक्षिक रिपोर्टें
14. आपातकालीन उपाय
15. सशस्त्र बल
16. निचली अदालतों (न्यायालयों) हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर करना और सजा बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में आवेदन करना।
17. सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालयों में विचारण के लिए लंबित अभियोजन मामलों को वापस लेना
18. साइफर संहिता (बीजलेख संहिता)
19. अपराधियों का प्रत्यर्पण
20. आंतरिक रेखा (लाइन) प्रतिबंध
21. मिशनरियों की नामित नामावली
22. विदेशियों की संपत्ति का क्रय
23. सेंसरशिप (सेंसर), नियंत्रण और आपत्तिजनक साहित्य का समपहरण (ज़ब्ती) सहित प्रेस नियंत्रण और अभियोजन।
24. विभिन्न विभागों से लोकसेवकों के विरुद्ध न्यायिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की सूचना का संग्रहण।
25. शिमला शहर की प्रतिबंधित/सील्ड सड़कों पर यानों को चलाने हेतु अनुज्ञप्ति जारी करना
26. हिमाचल प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1975 का क्रियान्वयन और प्रशासन
27. जेलों की स्थापना
28. कैदी पोषण, स्थानान्तरण और रिहाई
29. सुधार-गृह (सुधारक-स्कूल)
30. जेल विभाग की औद्योगिक इकाइयों का प्रशासन, अनुशासन और संचालन
31. न्यायिक-तालाबंदी
32. जेलों से सम्बन्धित स्थापन, बजट और लेखा मामले
33. भारतीय पुलिस सेवा

34. हिमाचल पुलिस सेवा
35. रक्षा उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण
36. संघ/राज्य युद्ध पुस्तक
37. अवैतनिक मजिस्ट्रेटों (न्यायाधीशों) की संस्था
38. हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय से मामलों आदि के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों को निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध करना।
39. राज्य में दांडिक और सिविल अधिकारिता के न्यायालयों का गठन, उनकी शक्तियाँ, रख-रखाव और संगठन सहित दांडिक और सिविल न्याय का प्रशासन।
40. महाधिवक्ता कार्यालय से सम्बन्धित समस्त संदर्भ जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय राज्य परिषद सूची तैयार करना सहित स्थापन और बजट मामले भी हैं।
41. भ्रष्टाचार के मामलों के विचारण (की सुनवाई) के लिए दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 के अधीन विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति।
42. उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापन और बजट मामलों आदि से संबंधित समस्त संदर्भ।
43. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन मामलों की सुनवाई (के विचारण) के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों (न्यायाधीशों) की शक्तियों का प्रत्यायोजन।
44. उच्चतर न्यायिक सेवा
45. न्यायिक सेवा
46. न्यायिक शक्तियों का प्रदत्त किया जाना
47. उच्च न्यायालय का गठन और संगठन
48. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र आदि, उनका वेतन, अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन और भत्तों की बाबत अधिकार।
49. न्यायिक और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण
50. शासकीय अधिवक्ताओं (प्लीडरों), लोक अभियोजकों, विशेष लोक अभियोजकों और जिला न्यायवादियों, अतिरिक्त जिला न्यायवादियों की नियुक्तियाँ, तैनाती, स्थानांतरण और अवकाश आदि।
51. सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार द्वारा दायर कार्यवाहियों पर आपराधिक मामलों की प्रतिरक्षा करना या को संस्थित करना, इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए सम्मन को ग्रहण करना।
52. सरकार के विरुद्ध या सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर सभी आपराधिक मामलों और कार्यवाहियों का अनुश्रवण।
53. अभियोजन निदेशालय की स्थापन और बजट से संबंधित समस्त मामले

### (ख) सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध

1. भ्रष्टाचार के उन्मूलन से संबंधित समस्त मामले
2. विभागीय जांच की प्रक्रिया में सभी विभागों को सहायता
3. सतर्कता आयोग और सतर्कता समिति
4. सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ईकाइयाँ
5. सतर्कता कार्य की रिपोर्ट और रिटर्न (विवरणियाँ)
6. जांच आयोग अधिनियम, 1952
7. स्थापन, बजट और लेखा मामले
8. समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 से संबंधित समस्त मामले।

### (ग) न्यायालयिक सेवाएं निदेशालय

1. न्यायालयिक शिक्षा, विकास और विस्तार सेवाएं और आई.ई.सी.
2. न्यायालयिक से संबंधित अधिनियमों का प्रवर्तन और प्रशासन
3. राज्य और केंद्र सरकार के अन्वेषण अभिकरणों (एजेंसियों), राज्य के अन्य विभागों और संस्थाओं जैसे न्यायालयों, आयोगों आदि और अन्य वैधानिक और संवैधानिक निकायों द्वारा संदर्भित मामलों का विश्लेषण।

4. अपराध स्थल (अवस्थान, संग्रहण, सुरागों का यथास्थान परिरक्षण) की जांच और अपराध स्थल का पुर्ननिर्माण।
5. विधिक न्यायालय, अन्य न्यायिक/अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के मामलों में दी गई रिपोर्ट की प्रतिरक्षा करना।
6. राज्य और केंद्र सरकार के सरकारी विभागों/संस्थानों द्वारा संदर्भित मामलों का गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण विश्लेषण।
7. न्यायालयिक मुद्दों पर सरकार को परामर्श देना, लोगोज और सरकारी दस्तावेजों में सुरक्षा सुविधाओं के लिए इनपुट प्रदान करना।
8. विधिक न्यायालयों और अन्य न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित/प्रतिपादित के अनुसार न्यायालयिक रिपोर्ट का मूल्यांकन।
9. न्यायपालिका, प्रशासन, पुलिस, अभियोजन आदि के अधिकारियों की कार्य क्षमता और न्यायालयिक ज्ञान और सार्वजनिक संपर्क का प्रसारण।
10. न्यायालयिक और मानव संसाधन विकास पर भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन सहित हिमाचल प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान विकास बोर्ड का इसके सभी कार्यों के लिए समर्थन करना।
11. विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, वार्तालाप की बैठकों आदि की व्यवस्था करना और उसमें भाग लेना।
12. न्यायालयिक से सम्बद्ध जर्नल, पत्रिकाओं और शोध पत्रों आदि का प्रकाशन
13. राज्य एफ.एस.एल. की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट और निर्देशिका को तैयार करना
14. हिमाचल प्रदेश न्यायालयिक सेवा संवर्ग का गठन और स्थापन
15. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ प्रभावी संपर्क और विभाग की क्षमताएं बनाए रखने के निर्माण में न्यायालयिक परियोजनाओं, अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग के कार्य करवाना।
16. अन्य सरकारी विभागों/संस्थानों आदि न्यायालयिक सेवा निदेशालय और भारत सरकार के अन्य संबद्ध निकायों और अन्य राज्यों के न्यायालयिक सेवा निदेशालयों से संपर्क।
17. आपदा में न्यायालयिक
18. राज्य के लिए न्यायालयिक नीति
19. स्थापन, बजट और लेखा मामले
20. राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, क्षेत्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला और नई विशेषताओं जैसे डिजिटल न्यायालयिक स्वर विश्लेषण आदि सहित उसमें स्थापित विभिन्न विशेषज्ञताओं और जिला मोबाईल न्यायालयिक इकाइयों तथा राज्य में राज्य उंगली छाप ब्यूरो की स्थापना के साथ और न्यायालयिक रिपोर्टों/परिणामों को जारी करने के लिए नियम और क्रिया विधि अधिकथित करना।

## 17. उद्यान विभाग

1. औद्यानिक विकास और विस्तार
2. औद्यानिक फसलों का पौध संरक्षण
3. संतति उद्यान और नर्सरी सहित उनका रजिस्ट्रीकरण और पर्यावेक्षण
4. फल विकास बोर्ड
5. कृषि-उद्योग निगम
6. फल और सब्जी परिरक्षण, शीतलन भण्डार (कोल्ड स्टोरेज), गोदाम और अन्य इकाइयां
7. औद्यानिक वृत्तियां और छात्रवृत्तियां
8. औद्यानिक ऋण और अग्रिम
9. फूलों की खेती और सजावटी बागवानी
10. मधुमक्खी पालन
11. औद्यानिकी पर विश्व बैंक परियोजना
12. औद्यानिकी में प्रशिक्षण
13. स्थापन, बजट और लेखा मामले
14. किसानों द्वारा जड़ी बूटियों की खेती और औषधीय सुगंधित पौधों का विकास

**18. आवास विभाग**

1. आवास बोर्ड द्वारा आरम्भ की जाने वाली योजनाएं।
2. अन्य सभी आवास योजनाएं, जैसे कि सब्सिडी वाली औद्योगिक आवास योजना, ग्राम आवास परियोजना स्कीमें और भूमिहीन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण आवास स्थल।

**19. उद्योग विभाग**

1. औद्योगिक सहकारिता के सिवाए सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की प्रगति और इसके अंतर्गत—
  - (क) रेशम उत्पादन— केन्द्रीय रेशम बोर्ड
  - (ख) खादी और ग्रामोद्योग — खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
  - (ग) हथकरघा — अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड
  - (घ) हस्तशिल्प — अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड
  - (ङ) लघु उद्योग
  - (च) मध्यम और बड़े उद्योग
  - (छ) विपणन और एम्पोरिया
  - (ज) औद्योगिक सम्पदा
  - (झ) औद्योगिक सर्वेक्षण
  - (ञ) ग्रामीण औद्योगिक परियोजना
  - (ट) उद्योगों को औद्योगिक और वित्तीय सहायता
  - (ठ) वन विभाग के अन्तर्गत के सिवाय सरकार के स्वामित्वाधीन औद्योगिक समुत्थान
2. फर्मों का रजिस्ट्रीकरण
3. भू-विज्ञान
4. खनन
5. औद्योगिक उद्यमों के लिए ऋण और अनुदान (सब्सिडी)
6. खान, खनिज, वित्तीय और औद्योगिक निगम
7. राज्य में व्यापार और वाणिज्य और भारी और लघु उद्योगों में विनिर्मित माल तथा उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय और वितरण।
8. स्थापन, बजट और लेखा मामले
9. बर्दादी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण और उससे सम्बद्ध मामले
10. संभार-तन्त्र (लॉजिस्टिक्स) क्षेत्र का एकीकृत विकास

**20. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग**

1. प्रैस, समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाएं
2. राज्य प्रसारणों सहित प्रकाशन और प्रचार
3. सरकारी नीतियों को अभिदर्शित करना
4. विज्ञापन
5. राज्य पत्रिकाओं का प्रकाशन
6. समुदाय संवाद योजना
7. स्थापन, बजट और लेखा मामले
8. गायन और नाटक योजना
9. सूचना केन्द्र स्कीम
10. प्रदर्शन स्कीम
11. मोबाइल सिनेमा स्कीम
12. फिल्म निर्माण स्कीम
13. फिल्म पॉलिसी, थिएटर खोलने आदि से सम्बन्धित समस्त मामले

## 21. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिसी की विरचना और कार्यान्वयन।
2. स्वचालन और साइबर नियन्त्रण प्रणाली की प्रस्तावना ताकि सरकारी स्तर पर तेजी से सूचना प्रसंस्करण सुनिश्चित हो सके और जिसके अन्तर्गत ई-गवर्नेंस से सम्बन्धित परियोजनाएं और क्रियाकलाप भी हैं।
3. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हार्डवेयर, साफ्टवेयर और विशेष रूप से आई.टी.ई.एस. और बी.पी.ओ. सेवाओं और सम्बन्धित क्रियाकलाप (गतिविधियां) निवेश को बढ़ावा देना तथा राज्य में सूचना प्रौद्योगिक अवसंरचना का सृजन और संवर्धन करना।
4. प्रमुख मापदण्डों का अनुश्रवण करना और विभिन्न विभागों और अर्ध-सरकारी संगठनों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सॉफ्टवेयर पैकज तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना।
5. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम अवसंरचना का उपयोग करके एकीकृत सेवा वितरण चैनल के माध्यम से सरकार – सार्वजनिक अन्तराणीक का सृजन करना और जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के फायदों पर जागरूकता अभियान भी शुरू करना।
6. विभागों/संगठनों के लिए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म का मानकीकरण करना और उनकी कीमतों का गत्यात्मक अनुश्रवण और फिजूल खर्च को कम करवाना सुनिश्चित करना।
7. हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का प्रशासनिक नियन्त्रण
8. राज्यव्यापी इन्टरनेट का कम से कम उपयोग करने के लिए कार्यनीति विरचित करना
9. संचार अवसंरचना से सम्बन्धित सूचना प्रौद्योगिकी का विकास
10. वेबसाइट के सृजन और अद्यतन करने में विभागों/अर्ध-सरकारी संगठनों की सहायता करना
11. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा का संवर्धन करना और शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों/अर्ध-सरकारी संगठनों में प्रशिक्षण देना और शैक्षणिक सॉफ्टवेयर को विकसित/प्रसारित करने की सुविधा देना तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा में कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
12. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों जैसी विभिन्न प्रोत्साहन सम्बन्धी गतिविधियों का आयोजन करना और उनमें भाग लेना।
13. भारत सरकार और उसके अभिकरणों (एजेंसियों) और इस क्षेत्र में भारत के साथ-साथ विदेशों में अन्य भागीदारों को भी प्रस्तुत सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित परियोजनाओं/स्कीमों का अनुपरीक्षण करना।
14. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की संवृद्धि के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा उद्यम पूंजी निधि स्थापन का सरलीकरण।
15. विधियों और नियमों की पहचान जिनके संव्यवहार के लिए सक्षम विधिक विधिमान्यता को उपांतरित या अधिनियमित करने की आवश्यकता है तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए विशिष्ट साइबर-कोडिंग विकसित करना भी आवश्यक है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य केन्द्रीय या राज्य विधानों से सम्बन्धित मामले के लिए राज्य सरकार की ओर से नोडल अभिकरण (एजेंसी)/प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।
16. राज्य में उपलब्ध समस्त सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सामग्री और मानव संसाधनों के लिए डेटाबेस का रखरखाव।

## 22. जल शक्ति विभाग

1. ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं और जल निकासी
2. शहरी डब्ल्यू.एस.एस. और जल निकासी/सीवरेज और स्वच्छता
3. लघु सिंचाई स्कीमें
4. बड़ी सिंचाई स्कीमें
5. मध्यम सिंचाई स्कीमें

6. बाढ़ नियंत्रण कार्य
7. कमान क्षेत्र विकास/चैक बांध संकर्म
8. एकीकृत बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनमें सिंचाई कार्यों का बड़ा हिस्सा शामिल है
9. अमेरिकी सहायता प्राप्त परियोजना कार्य और संबद्ध द्विपक्षीय विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
10. विभाग के लिए भूमि का अर्जन और उसके दावों का निपटान
11. मध्यस्थता के मामले
12. स्थापन बजट और लेखा मामले
13. सड़कों और नालों के किनारे मृदा (मिट्टी) संरक्षण कार्य

### 23. श्रम एवं रोजगार विभाग

#### (क) श्रम

1. निम्नलिखित का कार्यान्वयन और प्रशासन:—
  - (क) कारखाना अधिनियम, 1948
  - (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
  - (ग) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
  - (घ) भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926
  - (ङ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
  - (च) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
  - (छ) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923
  - (ज) कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, 1952
  - (झ) श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955
  - (ञ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
  - (ट) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
  - (ठ) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
  - (ड) बोनस संदाय अधिनियम, 1965
  - (ढ) बालक नियोजन अधिनियम, 1938
  - (ण) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
  - (त) बागान श्रम अधिनियम, 1951
  - (थ) व्यवसाय कर्मचारी अधिनियम, 1940
  - (द) औद्योगिक प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय और त्यौहार अवकाश और आकस्मिक और रूग्ण अवकाश अधिनियम, 1965
  - (ध) दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958
  - (न) श्रम विभाग के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पारित अन्य अधिनियम
2. श्रम सांख्यिकी
3. स्थापन, बजट और लेखा मामले
4. जनशक्ति और रोजगार स्कीमें:—
  - (क) रोजगार कार्यालय
  - (ख) रोजगार सेवा के आवृत्त का विस्तार
  - (ग) रोजगार बाज़ार की जानकारी का संग्रह
  - (घ) रोजगार कार्यालयों का कार्यान्वयन (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
  - (ङ) व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श
5. स्थापन, बजट और लेखा मामले

#### (ख) रोजगार

1. शिक्षता अधिनियम, 1961 के अधीन पदाभिहित व्यवसायों में शिक्षता प्रशिक्षण
2. जनशक्ति और रोजगार योजना:—
  - (क) रोजगार कार्यालय

- (ख) रोज़गार सेवा के आवृत्त का विस्तार
- (ग) रोज़गार बाज़ार की जानकारी का संग्रह
- (घ) रोज़गार कार्यालयों का कार्यान्वयन (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
- (ङ) व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोज़गार परामर्श
- (च) रोज़गार सृजन मानिटर करना और हिमाचल के स्थाई निवासियों को 70 प्रतिशत रोज़गार देना।

### 3. स्थापन, बजट और लेखा मामले

## 24. भाषा कला और संस्कृति विभाग

1. सांस्कृतिक मामलों से सम्बन्धित सभी मामले
2. सांस्कृतिक निकायों को सहायता अनुदान
3. भाषा:—
  - (i) भाषा नीति
  - (ii) राज भाषा का विकास
  - (iii) हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार करने से सम्बन्धित मामले
  - (iv) भाषा शिक्षण स्कीम
4. विभाग के स्थापन, बजट और लेखा मामले
5. म्यूजियम, पुरातत्व, पुरालेख (पुरालेखागार)
6. मंदिर, मेले और त्यौहार आदि

## 25. विधि एवं विधि परामर्शी विभाग

1. विधिक मामलों पर परामर्श
2. परिनियमों (स्टेट्यूट), अधिनियमों, विनियमों, वैधानिक नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की विरचना करना।
3. विधेयकों, अध्यादेशों, नियमों, उप-विधियों, अधिसूचनाओं और विनियमों का अभिहस्तांतरण लेखन और प्रारूपण।
4. सर्वोच्च न्यायालय में अपराधिक मामलों के सिवाय सरकार के विरुद्ध या सरकार द्वारा दायर किए गए वाद या कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा करना या संस्थित करना।
5. विधियों, नियमों और विनियमों का संहिताकरण
6. विधि विभाग पुस्तिका
7. केन्द्रीय अधिनियमों का राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में पुनर्प्रकाशन सहित भारत सरकार द्वारा यदि वांछित हो तो उनका हिंदी/पहाड़ी भाषा में अनुवाद का कार्य।
8. सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक मामलों के सिवाय सरकार के विरुद्ध सिविल, आपराधिक या रिट मामलों में उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जारी समन को ग्रहण करना।
9. प्रोबेट और प्रभासन के पत्रों और अनुरोध पत्रों तथा परिप्रश्नों को समुचित सम्बन्धित आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करना।
10. भारतीय विधि रिपोर्ट— मुद्रण, वितरण, प्रदाय, लेखापरीक्षा इत्यादि से सम्बद्ध प्रश्न
11. विधि परामर्शी कार्यालय — स्थापन एवं बजट से सम्बन्धित समस्त संदर्भ
12. शासकीय (आफिशियल) रिसीवर एवं नोटरी पब्लिक की नियुक्ति
13. राज्य विधि रिपोर्ट एवं विधि परामर्शी पुस्तकालय
14. भारत का संविधान— उससे सम्बन्धित सन्दर्भ
15. अधीनस्थ विधान समिति के साधारण प्रेक्षणों को एकत्रित/संकलित और अनुसरित करना
16. अधिनियमों, अध्यादेशों, विधेयकों, कानूनी नियमों, आदेशों, उप-विधियों, विनियमों का राजभाषा में अनुवाद।
17. अंग्रेज़ी में मूलरूप से अधिनियमित अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ का अधिप्रमाणीकरण तथा प्रकाशन।

18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों के अंग्रेजी पाठ का अधिप्रमाणन तथा प्रकाशन।

## 26. चिकित्सा शिक्षा विभाग

1. चिकित्सा शिक्षा/दंत शिक्षा अधिनियमों और नियमों का प्रशासन
2. चिकित्सा शिक्षा सेवाओं/दंत चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की विरचना और स्थापना
3. कार्मिकों के अभिनियोजन सहित हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/ हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त मामले।
4. राज्य में प्राइवेट चिकित्सा/दन्त/आयुर्वेद और अन्य सहबद्ध संस्थानों की स्थापना और प्रबन्धन से सम्बन्धित मामले।
5. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और दन्त महाविद्यालय तथा आयुर्वेदिक महाविद्यालय में शिक्षा और प्रशिक्षण
6. चिकित्सा/दन्त/आयुर्वेद से सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और चिकित्सा, दन्त और आयुर्वेद में सह-चिकित्सीय अनुशासनों और निम्नलिखित के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए नीति और कार्यक्रमों की विरचना:-  
 (क) आयुर्वेद शिक्षा सहित स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा/दन्त शिक्षा;  
 (ख) बी.एस.सी. स्तर तक नर्सिंग छात्र शिक्षा;  
 (ग) बी.एस.सी. प्रौद्योगिकी;  
 (घ) प्रयोगशाला तकनीशियन/रेडियोग्राफर आदि;  
 (ङ) ऑपरेशन थियेटर सहायक;  
 (च) भौतिक चिकित्सा और व्यवसायजन्य चिकित्सा (थैरेपी) और पुनर्वासन सेवाएं;  
 (छ) रक्ताधान सहायक;  
 (ज) स्वास्थ्य विज्ञानी और यन्त्रविद (दन्त);  
 (झ) रिफ्रेकशनिस्ट और नेत्र विज्ञानी सहायक;  
 (ञ) राज्य में चिकित्सा/दन्त/आयुर्वेदिक विषयों से सम्बन्धित विभिन्न संस्थानों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
7. राज्य में विभिन्न सरकारी चिकित्सा/दन्त और आयुर्वेदिक तथा सह-चिकित्सीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती और प्रोन्नति नियमों की विरचना।
8. राज्य से बाहर व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/दन्त शिक्षा/आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए नीति की विरचना।
9. निम्नलिखित के निर्धारण के लिए मानव संसाधन प्रबन्धन पर नीति की विरचना करना:-  
 (क) राज्य में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में अपेक्षित विभिन्न चिकित्सा/दन्त/आयुर्वेद सह-चिकित्सीय सेवाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति;  
 (ख) राज्य में और राज्य के बाहर दोनों जगह प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सम्मेलनों का आयोजन करना;  
 (ग) राज्य में चलाए जा रहे विभिन्न सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के लिए पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम;  
 (घ) चिकित्सा/दन्त/आयुर्वेद में उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए पुनश्चर्या आयोजित करना
10. भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद और सी.सी.आई.एम. और भारत सरकार के अन्य सहबद्ध निकायों के साथ सम्पर्क।
11. चिकित्सा और दन्त संस्थानों के स्थापन/बजट और लेखा मामले

## 27. बहुउद्देशीय परियोजनाएं और ऊर्जा विभाग

1. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 और भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 का प्रभासन एवं प्रवर्तन।
2. ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित पॉलिसी
3. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन और कार्यप्रणाली
4. टैरिफ पॉलिसी और विद्युत शुल्क



5. विद्युत निरीक्षणालय की स्थापना और इसका प्रशासन तथा नियन्त्रण
6. ऊर्जा और बहुदेशीय परियोजनाओं पर अन्तर्राज्यीय बैठकें और सम्मेलन
7. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के वार्षिक प्रशासनिक और वित्तीय रिपोर्ट (प्रतिवेदन)
8. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष को शक्तियों का प्रत्यायोजन
9. अन्तर्राज्यीय जल-विवाद और ऊर्जा एवं परियोजनाओं की संधियां/करार
10. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को अनुदान/ऋण और प्रत्याभूति आवश्यकताओं का निष्पादन।
11. संसद/विधानसभा प्रश्न, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन/आश्वासन समिति-उनसे सम्बन्धित कारबार।
12. परिषद के बजट अनुमान और वार्षिक लेखों को विधानसभा के सभापटल पर रखना
13. सरकारी विभागों और परिषद के बीच सम्पर्क करना
14. जनसाधारण और भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से विद्युत परिषद (बोर्ड) से सम्बन्धित विविध संदर्भ।
15. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अधीन दावे/निर्देश
16. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के लिए भूमि का अधिग्रहण
17. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की विभिन्न समितियों/परिषदों का गठन
18. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के नियमों की विरचना
19. नीतिगत विषय - हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को निर्देश देना
20. पंजाब राज्य विद्युत परिषद, हरियाणा राज्य विद्युत परिषद और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के मध्य आस्तियों और दायित्वों से सम्बन्धित विषय/मामले।
21. निम्नलिखित का प्रशासनिक नियन्त्रण:-
  - (i) हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
  - (ii) हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, और
  - (iii) ऊर्जा निदेशालय।
22. सरकारी/प्राइवेट/संयुक्त/केन्द्रीय सेक्टर की जल विद्युत परियोजनाओं का विकास

## 28. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

1. निम्नलिखित से सम्बन्धित पॉलिसियों, योजनाओं, अधिनियमों और नियमों के अनुसार कार्रवाई करना:-
  - (i) सौर ऊर्जा जिसके अन्तर्गत फोटोवोल्टिक उपकरण भी है;
  - (ii) समुन्नत चूल्हे और इनका अनुसंधान एवं विकास;
  - (iii) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.);
  - (iv) भू-तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा; और
  - (v) अन्य अपारम्परिक/नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।
2. हिम ऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) का प्रशासनिक नियन्त्रण।

## 29. पंचायती राज विभाग

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियम
2. ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की स्थापना तथा उनका गठन
3. पंचायतों का पुनर्गठन और उनका विभाजन
4. पंचायती राज संस्थाओं का नियन्त्रण, निरीक्षण और पर्यवेक्षण
5. पंचायती राज निकायों के बजट, लेखों और व्यय की संवीक्षा और उनका अनुमोदन
6. पंचायती राज निकायों के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें और उनकी जांच
7. पंचायती राज निकायों के लेखों की संपरीक्षा
8. पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान।

9. पंचायती राज से सम्बद्ध पत्र-पत्रिकाओं (जर्नल) और अन्य नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन।
10. विभाग के बजट, लेखों और स्थापन के मामले
11. पंचायती राज निकायों को अनुदान
12. राज्य निर्वाचन आयोग:-
  - (i) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन
  - (ii) स्थानीय निकायों के निर्वाचन
  - (iii) गुरुद्वारों के निर्वाचन

### 30. संसदीय मामले विभाग

1. मन्त्रियों द्वारा सदन के पटल पर दिए आश्वासन — नीति और समन्वयन
2. विधानसभा को और से निर्देश
3. विधानसभा सदस्यों के निरर्हता का निवारण और इससे सम्बन्धित मामले
4. मुख्य सचेतकों/सचेतकों के सम्मेलन
5. विधान मण्डल समितियों से सम्बन्धित कार्य
6. सरकार द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधान सभा सदस्यों (एम.एल.एज़.) की नियुक्ति करना।

### 31. कार्मिक विभाग

#### (क) नियुक्ति

1. अखिल भारतीय सेवाएं — कार्मिकों से सम्बन्धित सामान्य मामले
2. भारतीय प्रशासनिक सेवाएं
3. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अधिक्रमण के मामले
4. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं
5. विभागाध्यक्षों की नियुक्तियां
6. संवर्ग अधिकारियों से अन्यथा उप-सचिव और अवर सचिव
7. लोक सेवा आयोग:-
  - (i) कृत्य और उसकी परिसीमाएं
  - (ii) स्थापन, बजट, लेखे और अन्य मामले
8. अनुकम्पा आधार पर नियोजन सहायता उपलब्ध करवाने के सिवाय भर्ती और प्रोन्नति से सम्बन्धित सभी नीतिगत मामले।
9. सभी विभागों की सेवाओं के नियम
10. सरकारी सेवकों के दण्ड और अपील के नियम
11. सेवा मामलों से सम्बन्धित नीति:-
  - (i) चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन
  - (ii) तैनाती और स्थानान्तरण
  - (iii) रियायतें
  - (iv) विवाह
  - (v) आकस्मिक अवकाश
  - (vi) सेवानिवृत्ति
  - (vii) गोपनीय रिपोर्ट
  - (viii) जन्म तिथि (परिवर्तन)
  - (ix) पदों को राजपत्रित घोषित करना
  - (x) विभागीय परीक्षा
  - (xi) प्रतिनियुक्ति
  - (xii) दक्षतारोध
  - (xiii) चिकित्सा प्रमाण पत्र

- (xiv) अभ्यावेदन
- (xv) पुनर्नियोजन
- (xvi) वरिष्ठता और स्थायीकरण

12. सेवा संगम
13. निम्न की नियुक्ति:-
  - (i) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (यदि अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा कॉडर से है) और कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) (यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए);
  - (ii) अधिनियम/परिनियम के अधीन गठित निगमों और हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक;
  - (iii) नगर निगम के प्रशासक;
  - (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य आवास बोर्ड का अध्यक्ष, सदस्य और सचिव
14. निर्देशिकाएं और वार्षिक पुस्तिका – उनका पुनरीक्षण
15. प्रशासनिक सचिवों के मध्य विषयों का आबंटन
16. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग – से सम्बद्ध समस्त विषय

### (ख) सचिवालय प्रशासन

1. हिमाचल प्रदेश सचिवालय के स्थापन के अनुभाग अधिकारियों के स्तर तक की नियुक्ति, प्रोन्नति, तैनाती और स्थानान्तरण, वेतन, छुट्टी, भर्ती आदि से सम्बन्धित समस्त मामले।
2. सचिवालय पुस्तकालय
3. सचिवालय में दूरभाष
4. सचिवालय कर्मचारिवृन्द के गृह प्रबंधन कर्तव्य (हाऊस कीपिंग)
5. सचिवालय प्रशासन का बजट और लेखे

### (ग) प्रशासनिक सुधार

1. प्रशासनिक सुधारों पर सचिवों की समिति
2. ऐसे क्षेत्रों की साधन के रूप में पहचान करते हुए नियोजित पुनर्विलोकन के कार्यक्रम आरंभ करना जिनका विस्तृत अध्ययन संभाव्यतः प्रशासन में सुधार, दक्षता और मितव्ययिता लाने में महत्वपूर्ण और प्रभावी सिद्ध (साबित) हो।
3. संगठनों और कार्यप्रणाली की पद्धति के अध्ययन का जिम्मा
4. नई स्कीमों के अन्तर्गत जिनमें नए पदों की बहुसंख्य अन्तर्वलित है, कर्मचारिवृन्द की अपेक्षाओं का निर्धारण।
5. कार्य मानकों का मूल्यांकन
6. निम्न के लिए वित्तीय और सजातीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए स्कीम बनाना:-
  - (i) सरकार के प्रशासनिक विभाग;
  - (ii) विभागों के कार्यकारी अध्यक्ष; और
  - (iii) कार्यकारी अध्यक्षों के अधीनस्थ क्षेत्रीय अधिकारी।
7. विभागीय निर्देशिकाएं पुस्तिका, स्थाई आदेश, संरक्षण नस्तियां आदि को तैयार करने की व्यवस्था
8. विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए उचित प्रपत्र तैयार करना
9. विहित नियमों और प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और सांकेतिक परीक्षाओं का जिम्मा।

### (घ) प्रशिक्षण

1. हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों सहित इसका बजट, लेखे, स्थापन आदि।

2. हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों सेमीनारों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और सेवाओं/विभागों जो सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान को समनुदेशित किए जाएं, की विभागीय परीक्षाओं का संचालन करना।
3. नियमों, नियमावलियों, संहिताओं आदि का पुनरीक्षण
4. लोक प्रशासन से सम्बन्धित अनुसंधान एवं प्रकाशन
5. प्रबन्धन तकनीकों में परामर्शक और सलाहकारी सेवाएं
6. विदेश के प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धित सभी मामले
7. शासकीय प्रतिनिधि मण्डलों जिनमें राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त बोर्डों के अधिकारी सम्मिलित हैं, की विदेश यात्राएं।

#### (ड) प्रशासनिक योजना और मूल्यांकन

1. सरकारी उप व्यवस्था में ऐसे क्षेत्रों, जहां संगठनात्मक ढांचे और प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है, की पहचान के लिए कार्यबलों की स्थापना करना।
2. नियंत्रण प्रणाली का पुनरीक्षण करना ताकि सभी स्तरों पर विलम्ब को रोका जा सके और अवसरों और प्रयोजनों, जिनके लिए नागरिकों को सरकार से सम्पर्क करना पड़ता है, की संख्या कम करना।
3. सरकार में सभी स्तरों पर समुचित प्रत्यायोजन के माध्यम से विनिश्चय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना।
4. मूल्यांकन पालन प्रारम्भ करना ताकि उत्तरदायी प्रबन्धन और दायित्व क्षेत्रों का नियतन सुनिश्चित किया जा सके।

### 32. योजना विभाग

#### (क) योजना

1. योजना बनाने से सम्बन्धित समस्त मामले जिसके अन्तर्गत वित्त विभाग के परामर्श से संसाधनों का आंकलन करना, प्राथमिकताएं अधिकथित करना, योजना लक्ष्य नियत करना और संसाधनों को निश्चित करना किन्तु जहां मामले जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हों तो उस दशा में जनजातीय विकास विभाग से परामर्श करना होगा।
2. योजना समन्वयन और योजना कार्यक्रमों के कालिक पुनरीक्षण से सम्बद्ध मामले किन्तु जनजातीय उप-योजना और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना से सम्बन्धित मामलों में जनजातीय विकास विभाग से परामर्श किया जाएगा।
3. योजना स्कीमों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना किन्तु जनजातीय उप योजना और अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के सम्बन्ध में जनजातीय विकास विभाग से परामर्श किया जाएगा।
4. चालू योजना स्कीमों का समय-समय पर युक्तिकरण और नई योजना स्कीमों को प्रारम्भ करना
5. बाह्य सहायता-प्राप्त समस्त योजनाओं के लिए समन्वय और संपर्क सम्बन्धी मामले
6. केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय सैक्टर कार्यक्रम, जिनमें प्रतिस्थानी राज्य का वित्तपोषण अर्न्तवर्तित है, से सम्बन्धित समस्त मामले।
7. योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से समन्वय और सम्पर्क करने से सम्बन्धित समस्त मामले।
8. राज्य योजना बोर्ड से सम्बन्धित समस्त मामले
9. जिला स्तरीय योजना विकास और बीस सूत्रीय कार्यक्रम पुनर्विलोकन समितियों के गठन से सम्बन्धित समस्त मामले।
10. योजना विकास, बीस सूत्रीय कार्यक्रम पुनर्विलोकन और लोक शिकायत निवारण पर उप-मण्डल स्तरीय समितियों की स्थापना से सम्बन्धित समस्त मामले।
11. निष्क्रिय परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए नाबार्ड (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) की रिडफ (आर.आई.डी.एफ.) प्रसुविधा के अन्तर्गत (आर.आई.डी.एफ.) वित्तपोषण (फंडिंग) की पालिसी सहित समस्त मामले।
12. जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के सिवाय योजना से सम्बन्धित मामलों पर समस्त विभागों को परामर्श (सलाह) देना।

13. विभिन्न विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रमों, जैसे विकास में 'जन' सहयोग, सेक्टरल विकेन्द्रीकृत योजना, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना आदि, का प्रतिपादन करना, उनमें समन्वय करना और उनकी समीक्षा करना।
14. राज्य स्तर पर एम.पी. स्थानीय क्षेत्रीय विकास स्कीम का समन्वयन करना
15. पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना से सम्बन्धित समस्त मामले
16. जनशक्ति और नियोजन योजना के समन्वय से सम्बन्धित समस्त मामले
17. अल्प संख्यकों के लिए 15 बिन्दु कार्यक्रम के बिन्दु 13 के अन्तर्गत आर्थिक पहलुओं के समन्वय से सम्बन्धित मामले।
18. कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना के समन्वय से सम्बन्धित मामले
19. विभिन्न विभागों से सम्बन्धित बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन का समन्वयन
20. विभिन्न सेक्टरों में परिप्रेक्ष्य नियोजन, समन्वयन और विभिन्न विभागों को परामर्श देने से सम्बन्धित समस्त मामले।
21. राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों के कार्यान्वयन का समन्वयन
22. विधायकों की प्राथमिकताओं पर पत्राचार और उनका समन्वयन और पुनर्विलोकन
23. विभिन्न बैंकों की ऋण योजनाओं का समन्वयन

#### (ख) अर्थ एवं सांख्यिकी

1. राज्य आय की संगणना
2. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण
3. सामुदायिक विकास के आंकड़े और प्रगति रिपोर्टें
4. कर्मचारियों की जनगणना
5. शासकीय सांख्यिकी
6. मूल्य सांख्यिकी
7. श्रम सांख्यिकी
8. कारखाना सांख्यिकी
9. सांख्यिकीय प्रशिक्षण
10. कार्यक्रमों का मूल्यांकन
11. विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों का समन्वयन
12. ग्राम निर्देशिका
13. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
14. जिला सुशासन सूचकांक (डी.जी.जी.आई.)

#### (ग) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी
2. बीस सूत्रीय कार्यक्रम का मूल्यांकन

### 33. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

1. प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट)
2. सरकारी मुद्रण कार्य
3. सरकारी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री का उपापन और आपूर्ति
4. सरकारी प्रकाशनों और राजपत्रों की आपूर्ति
5. विभाग के स्थापन, बजट और लेखा मामले

### 34. लोक निर्माण विभाग

1. सरकारी भवनों का निर्माण और उनका अनुरक्षण

2. सरकारी भवनों का एक विभाग से दूसरे विभाग को अन्तरण
3. सड़कों और सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण और दावों का निपटारा
4. राज्य में सड़कों, पुलों, तरणियों, सुरंगों, रज्जू मार्गों, पैदल मार्गों (कॉज़वेज़) और अन्य संचार साधनों का निर्माण।
5. आंतरिक जल मार्ग
6. पुलों पर पथकर
7. भवन और सड़क बोर्ड
8. स्थापन, बजट और लेखा मामले
9. हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिभोग में भारत सरकार के भवनों से संबंधित मामले

### 35. लोक शिकायत निवारण विभाग

1. समस्त मन्त्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण तन्त्र स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश अधिकथित करना और इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करवाना।
2. शिकायतों के निवारण के लिए एक विकेन्द्रीकृत तन्त्र की स्थापना सुनिश्चित करना, इसका प्रभावी कार्यकरण करना, व्यवस्थित परिवर्तन के लिए शिकायत-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना और शिकायत प्रबन्धन कार्य को कम्प्यूटरीकृत करना।
3. शिकायत निवारण में सहायता करने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों से सम्पर्क करना।
4. मन्त्रालयों/विभागों/संगठनों और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा चार्टर को तैनात करने के लिए सूचना सांझा करके क्रियाकलाप समन्वय करके नागरिक चार्टर विरचित करने के लिए दिशा-निर्देश अधिकथित करना।
5. मन्त्रालयों/विभागों में सूचना और सुविधा काउंटर (आई.एफ.सी.) स्थापित करने में समन्वय करना
6. मन्त्रालयों/विभागों के शिकायत निवारण तन्त्र और विभिन्न नागरिक चार्टरों और आई.एफ.सी. का प्रचार करना।
7. माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा आबंटित कोई अन्य कार्य
8. हिमाचल प्रदेश की आम जनता से अभिप्राप्त अभिवेदन

### 36. राजस्व विभाग

#### (क) भू-राजस्व

1. तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का स्थापन
2. भू-राजस्व स्थापन
3. 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत जिला स्थापन
4. नायब-तहसीलदारों, तहसीलदारों और अतिरिक्त-सहायक आयुक्त की विभागीय परीक्षा
5. बन्दोबस्त प्रवर्तन एवं इसके स्थापन
6. राजस्व अपीलें
7. नौतोड़, वाटर मिल्स, सांपत्तिक अधिकार की स्वीकृति
8. लघु नहर अधिनियम और नियम का प्रशासन
9. भूमि अधिग्रहण कार्य सहित विभिन्न परियोजनाएं तथा उनसे सम्बन्धित मामले
10. स्टाम्प
11. राजस्व की वसूली
12. ऋण एवं परिदान
13. नए नगर के निर्माण, भूखण्डों का विक्रय आदि से सम्बन्धित नीति विषयक मामले
14. प्रतिपाल्य अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्ड्स)
15. विविध मामले जिसके अन्तर्गत:-
  - (क) नौतोड़ मामले
  - (ख) सरकारी भूमि का अन्तरण
  - (ग) भूमि की नीलामी

- (घ) अधिक्रमण मामले
- (ङ) लम्बरदारी से सम्बन्धित मामले
- (च) उपकरणों की दर
- (छ) सरकारी देयों की वसूली
- (ज) अवसूलीय बकायों को बट्टे-खाते में डालना
- (झ) जागीर एवं मौफी सम्बन्धित मामला
- (ञ) भू-राजस्व का आस्थगन और छूट
- (ट) भू-राजस्व का निर्धारण और बातिलीकरण
- (ठ) अभिघृति सम्बन्धित मामले
- (ड) राजस्व अधिकारियों की कारबार विवरणियां और राजस्व न्यायालय के मामले
- (ढ) कृष्य भूमि उपयोगिता आदेश

16. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले।

### (ख) भू-अभिलेख

1. रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण पुस्तिका
2. वार्षिक और ऋतु-कालिक फसल रिपोर्ट
3. कृषि सांख्यिकी
4. मौसम सांख्यिकी और रिपोर्टें
5. राजस्व कारबार एवं विवरणियां
6. कानूनगों और पटवारियों का प्रशिक्षण और परीक्षा
7. भू-अभिलेख
8. नायब-तहसीलदार परीक्षाएं
9. पूर्वानुमान रिपोर्ट
10. फसल कटाई परीक्षण
11. खेतीहर (कृषि) मजदूरी
12. खेती (फसल) काटने/एकत्र करने का दाम
13. अरजी लेखक परीक्षा और लिपिकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रशिक्षण और उनकी परीक्षाएं
14. वर्ग "ए" नायब-तहसीलदारों और तहसीलदार के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण
15. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले

### (ग) जिला गैजेटियर

जिला गैजेटियरों को तैयार करना और उनका पुनरीक्षण करना।

### (घ) भू-एकत्रीकरण

1. भू-एकत्रीकरण संचालनों से सम्बन्धित समस्त मामले
2. भूमि-बन्दोबस्त
3. स्थापन, बजट और लेखा मामले

### (ङ) उपनिवेशन (बस्तियां)

1. सरकारी भूमि का उपनिवेशन
2. नई मण्डियों और कारखाना क्षेत्रों आदि का विकास

### (च) राहत, पुनर्वास एवं आपदा प्रबन्धन

1. अर्जित निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन, प्रबन्धन, पट्टे पर देना और आबंटन करना।

2. भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दो संपुटित सौदा द्वारा निपटान के लिए अन्तरित अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी निष्क्रान्त सम्पत्तियों का निपटान।
3. बे-घर हुए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित उनको राहत प्रदान करना और उनका पुनर्वासन करना।
4. विभिन्न प्रकार के ग्रामीण और शहरी ऋणों की वसूली का स्थगन, उनका उत्सादन और उन्हें बट्टे खाते में डालना तथा अन्य पुनर्वास देयों की वसूली
5. मुख्य परियोजनाओं से बेदखल हुए व्यक्तियों का पुनर्वास
6. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
7. वक्फ सम्पत्ति का प्रशासन

### (छ) भूमि सुधार

1. भूमि सुधार विधियों का क्रियान्वयन
2. भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियम और सहबद्ध मामले
3. प्रतिकर अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण
4. बड़ी जमींदारी सम्पदाओं का उन्मूलन और भूमि-सुधार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर अधिकारियों की नियुक्ति।
5. अपीलीय कार्य
6. स्थापन बजट और लेखा मामले

### (ज) प्राकृतिक आपदा

1. बाढ़, अकाल और सूखा, आग, भूकम्प, हिमस्खलन, ओलावृष्टि आदि से पीड़ितों को राहत
2. पीड़ितों को आनुग्रहिक राहत प्रदान करना और उन्हें ऋण देना
3. पीड़ितों से ऋणों और अन्य देयों की वसूली को आस्थगित करना/छूट देना/ स्थगन करना
4. पीड़ितों को राहत और सहायता उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
5. पीड़ितों का पुनर्वास

## 37. ग्रामीण विकास विभाग

1. विकास खण्ड
2. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत टी.आर.वाई.एस.ई.एम. एवं डी. डब्ल्यू.सी.आर.ए. (ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास) भी हैं।
3. विस्तारित आई.आर.डी. कार्यक्रम
4. जवाहर रोजगार योजना जिसके अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना, मिलियन वेलस स्कीम, विशेष अभिनव परियोजनाएं भी हैं।
5. रोजगार आश्वासन योजना
6. बंजर-भूमि विकास परियोजनाएं
7. माइक्रो वाटरशेड परियोजनाएं
8. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम
9. मरुस्थल विकास कार्यक्रम
10. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत राज्य योजना एवं केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना भी है।
11. गांधी कुटीर योजना
12. केन्द्रीय ग्रामीण-आवास योजना
13. ग्रामीण कारीगरों को नवीनतम उपकरण किट की आपूर्ति
14. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना



15. समुन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम
16. ग्रामीण विकास के राज्य संस्थान
17. सिलाई केन्द्र
18. सामाजिक शिक्षा, महिला मण्डलों और युवा मण्डलों आदि का संगठन
19. पुराने कुहलों का नवीनीकरण और पुर्ननिर्माण
20. मन्त्रियों द्वारा वैवेविक अनुदान
21. विभाग का बजट, लेखा एवं स्थापन मामले
22. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित क्रेडिट-कम-सब्सिडी योजना जिसके अन्तर्गत निम्न आय समूह आवास योजना और मध्यम आय समूह आवास योजना भी हैं।

### 38. सैनिक कल्याण विभाग

1. सेना के साथ संपर्क
2. राष्ट्रीय रक्षा कोष (निधि)
3. छावनी से सम्बन्धित मामले
4. सैनिक कल्याण
5. एल.एस.एस. शिविर एवं प्रादेशिक सेना
6. राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में प्रवेश के लिए हिमाचल प्रदेश से अभ्यर्थियों का चयन।
7. झण्डा दिवस का अनुपालन
8. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए विशेष निधि का प्रशासन
9. हिमाचल प्रदेश रक्षा और सुरक्षा राहत कोष का प्रशासन
10. मुख्यमंत्री सैनिक सुख सुविधा निधि को प्रशासन
11. युद्ध जागीर

### 39. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

#### (क) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले

1. छुआछूत, भिक्षावृत्ति और अन्य सामाजिक अक्षमताओं को दूर करना
2. परिवीक्षणीय सेवाएं
3. कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन,—  
(क) अनुसूचित जाति  
(ख) पिछड़ा वर्ग जिसके अन्तर्गत अधिसूचित समुदाय भी हैं  
(ग) वृद्ध एवं दुर्बल  
(घ) दिव्यांगजन
4. स्वैच्छिक कल्याण संगठन—क्षेत्र परामर्श और वित्तीय सहायता
5. तिब्बती शरणार्थी
6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन
7. सामाजिक सुरक्षा उपाय
8. स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
9. पंजाब, जम्मू और कश्मीर के आप्रवासी और सहबद्ध मामले
10. अनुसूचित जातियों की बाबत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
11. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
12. हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1979
13. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
14. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979।
15. अल्पसंख्यकों का कल्याण।
16. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

17. नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम
18. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) निगम/अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) आयोग
19. अनुसूचित जाति उपयोजना
20. अनुवर्ती कार्यक्रम

#### (ख) महिला एवं बाल विकास

1. महिलाओं और बालकों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रम
2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
3. मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना
4. माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना
5. एकीकृत बाल विकास योजना सेवा (आई.सी.डी.एस.)
6. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)
7. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)
8. किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गान्धी योजना (सबला)
9. मदर टेरेसा मातृ संबल योजना
10. बेटी है अनमोल
11. बलात्कार पीड़िता एवं यौन कार्यकर्ताओं (सेक्स वर्कर) के लिए पुनर्वास योजना
12. महिलाओं एवं बच्चों की अनैतिक तस्करी को अलग करना
13. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
14. किशोर न्याय अधिनियम, 2006
15. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
16. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
17. लैंगिक असमानता (जेंडर बजटिंग)
18. महिला विकास निगम
19. राज्य महिला आयोग
20. हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद
21. स्थापन बजट एवं लेखा मामले
22. महिलाओं/विधवाओं के लिए नारी सेवा सदन
23. महिलाओं के लिए पुनर्विवाह और स्वरोजगार आदि
24. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड
25. स्वैच्छिक कल्याण संगठन-क्षेत्र परामर्श और वित्त सहायता

#### 40. तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

1. तकनीकी शिक्षा
2. तकनीकी जनशक्ति का प्रशिक्षण
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
4. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना।
5. ग्रामीण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
6. तकनीकी जनशक्ति के लिए योजना
7. तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का कौशल विकास कार्यक्रम और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वय के लिए प्रशासनिक विभाग के रूप में कृत्य करना।

**41. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग**

1. पर्यटन का विकास और संवर्धन
2. राज्य और जिला पर्यटक सलाहकार समितियां
3. पर्यटन सेवाएं/सूचना का प्रदाय, आवास का आरक्षण और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था
4. होटल व्यवस्थापन
5. विभागीय पर्यटन आवास का सन्निर्माण/रखरखाव
6. खेल जैसे कि शीतकालीन खेल, गोल्फ, बोट क्लब आदि
7. यात्रा अभिकर्ताओं (ट्रैवल एजेंटों) और शिकार अभिकर्ताओं को मान्यता
8. हिमाचल प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग से सम्बन्धित मामले
9. स्थापन बजट एवं लेखा मामले
10. जीवाश्म पार्क और खाद्य शिल्प संस्थान
11. हिमाचल प्रदेश में झीलों का विकास
12. नागरिक उड्डयन और फ्लाईंग क्लब जिसके अन्तर्गत फ्लाईंग प्रशिक्षण (ट्रेनिंग), एयरो स्पोर्ट्स संस्थान, हँग ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) और प्रतियोगिताएं, हवाई पट्टियों के लिए स्थल (साइट) चयन, हेलीकॉप्टर सेवाएं, एयर-क्राफ्ट ऑपरेशन, हेलीपैडों को अभ्युत्थान।

**42. नगर एवं ग्राम योजना विभाग**

1. स्थापन एवं बजट मामलों आदि से सम्बन्धित समस्त संदर्भ और इसके अधीनस्थ कार्यालय
2. सुधार न्यास और विकास प्राधिकरण

**43. परिवहन विभाग**

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 और तदधीन बनाए गए नियम
2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 और तदधीन बनाए गए नियम
3. हिमाचल पथ परिवहन निगम और उससे सम्बद्ध समस्त मामले
4. हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और उससे सम्बद्ध समस्त मामले।
5. यात्रियों और माल परिवहन के लिए मोटर वाहनों के विनियमन और समस्त सहबद्ध मामले
6. राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण
7. जल परिवहन और उससे सहबद्ध समस्त मामले
8. सड़क किनारे बस/वर्षा शालिकाओं का प्रबन्धन और विकास
9. हिमाचल प्रदेश मोटरयान (कराधान) अधिनियम, 1972 और उसका प्रशासन
10. हिमाचल प्रदेश में रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी करने से सम्बन्धित समस्त मामले
11. अतिरिक्त माल कर के सिवाय यात्री और माल कर

**44. जनजातीय विकास विभाग**

1. साधारणतः योजना से सम्बन्धित समस्त मामले, अर्थात् राज्य के जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को प्रभावित करने वाले मामलों के सम्बन्ध में संसाधनों का आकलन, योजनाओं की विरचना, लक्ष्य और भौतिक पहलुओं को अधिकथित करना तथा समन्वय करना।
2. राज्य के जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रभावित करने वाले मामलों के सम्बन्ध में योजना गतिविधियों का कालिक निर्धारण और मूल्यांकन।

3. जनजातीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली नई स्कीमों को प्रारम्भ करने सहित समस्त पालिसी मामलों के साथ-साथ जनजातीय विभाग के साथ समस्त प्रशासनिक विभागों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से सम्बन्धित मामलों पर उनसे परामर्श करना।
4. राज्य के जनजातीय क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रभावित करने वाले मामलों के सम्बन्ध में किसी अन्य विभाग से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव को विभागों से सम्यक् परामर्श और करारों के पश्चात आरम्भ करना।
5. राज्य के जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रभावित करने वाले मामलों के सम्बन्ध में सभी विभागों को सलाह देना।
6. राज्य के जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रभावित करने वाले मामले के सम्बन्ध में किसी भी विभाग के समस्त क्रियाकलापों (गतिविधियों) का समग्र समन्वय और मूल्यांकन।
7. जनजातीय सलाहकार परिषद
8. एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं
9. जनजातीय विकास विभाग के स्थापन, बजट एवं लेखा मामले
10. हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968
11. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
12. अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
13. अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियन्त्रण जिसके अन्तर्गत इकहरी लाइन प्रशासन भी है।
14. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त मामले जिसके अन्तर्गत नीति भी है

#### 45. शहरी विकास विभाग

1. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित अधिनियम और नियमों का प्रशासन
2. स्थानीय निकायों का बजट और लेखे
3. स्थानीय निकायों के कराधान प्रस्ताव
4. स्थानीय निकायों की स्थापना
5. लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टें
6. स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान और ऋण
7. जनसाधारण के लिए नागरिक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था और स्थानीय निकायों के मामलों का प्रबन्धन।
8. गन्दी बस्ती निकासी और सीवरेज निपटान स्कीमें
9. अधिसूचित और नगरपालिका क्षेत्र में कल्याण स्कीमें
10. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित सेमिनार, सम्मेलन
11. नगरपालिका के कर्मचारियों का प्रशिक्षण
12. मवेशी अतिचार आदि
13. स्थापना, बजट और लेखा मामले
14. शहरी विकास
15. झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों के लिए स्वामित्व अधिकार, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और उनसे सम्बद्ध मामले
16. शहरी सम्पदा मनाली और मनु मार्केट मनाली

#### 46. युवा सेवा एवं खेल विभाग

1. युवा-सेवा और खेल-कूद के लिए कार्यक्रमों की विरचना, कार्यान्वयन और समन्वय
2. विकास कार्यक्रमों में युवकों की भागीदारी और बीस सूत्री कार्यक्रम
3. युवकों के संगठन और शिक्षित बेरोजगारों की समस्या से निपटने के लिए अवसंरचनात्मक सहायता की व्यवस्था।

4. खेलकूद परिषद से सम्बन्धित मामले
5. खेलकूद के विकास और संवर्धन से सम्बन्धित समस्त मामले
6. पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली

-----

*[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD-C-A(3)-2/2019 dated 10th December, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
(Confidential & Cabinet)**

NOTIFICATION

*Shimla-171002, 10th December, 2021*

**No. GAD-C-A(3)2/2019.**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 166 of the Constitution of India the Governor of Himachal Pradesh hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**2. Allocation of business.**—(1) The entire Business of the Government shall be transacted in the Departments of Himachal Pradesh as specified in the SCHEDULE-'A' and 'B' and shall be classified and distributed between those Departments as laid down therein.

(2) There shall be a Secretary for each Department who shall be the official Head of the Department:

Provided that –

- (a) more than one Department may be placed in the charge of the same Secretary;
- (b) the work of the Department may be divided between two or more Secretaries.

**3. Repeal and savings.**—(1) The Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971 notified *vide* Notification No. 5-2/71-GAD(CC), dated 25th January, 1971 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order of the Governor,

RAM SUBHAG SINGH,  
Chief Secretary.

## SCHEDULE A

## LIST OF DEPARTMENTS

Sl. No. 1	Name of the Department 2
1.	Agriculture Department
2.	Animal Husbandry Department
3.	Ayush Department
4.	Co-operation Department
5.	Election Department
6.	Elementary Education Department
7.	Environment, Science and Technology Department
8.	Department of State Taxes and Excise
9.	Finance Department
	(a) Finance
	(b) Himachal Pradesh State Audit Department
	(c) Treasuries, Accounts and Lotteries
10.	Fisheries Department
11.	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department
12.	Forest Department
13.	General Administration Department
	(a) General, Political and Miscellaneous
	(b) Confidential and Cabinet
	(c) Hospitality and Protocol
14.	Health and Family Welfare Department
15.	Higher Education Department
16.	Home Department
	(a) Home
	(b) Vigilance and Anti Corruption
	(c) Directorate of Forensics Services
17.	Horticulture Department
18.	Housing Department
19.	Industries Department
20.	Information and Public Relations Department
21.	Information Technology Department
22.	Jal Shakti Vibhag
23.	Labour and Employment Department
	(a) Labour
	(b) Employment
24.	Language, Arts and Culture Department
25.	Law and Legal Remembrancer's Department
26.	Medical Education Department
27.	MPP and Power Department
28.	Non-Conventional Energy Sources Department
29.	Panchayati Raj Department
30.	Parliamentary Affairs Department
31.	Personnel Department:
	(a) Appointment
	(b) Secretariat Administration
	(c) Administrative Reforms

- (d) Training
- (e) Administrative Planning and Evaluation
- 32. Planning Department:
  - (a) Planning
  - (b) Economics and Statistics
  - (c) 20-Point Programme
- 33. Printing and Stationery Department
- 34. Public Works Department
- 35. Redressal of Public Grievances Department
- 36. Revenue Department
  - (a) Land Revenue
  - (b) Land Records
  - (c) District Gazetteer
  - (d) Consolidation of Holdings
  - (e) Colonisation
  - (f) Relief, Rehabilitation and Disaster Management
  - (g) Land Reforms
  - (h) Natural Calamities
- 37. Rural Development Department
- 38. Sainik Welfare Department
- 39. Social Justice and Empowerment Department
  - (a) Scheduled Caste, Other Backward Classes and Minorities Affairs
  - (b) Women and Child Development
- 40. Technical Education, Vocational and Industrial Training Department
- 41. Tourism and Civil Aviation Department
- 42. Town and Country Planning Department
- 43. Transport Department
- 44. Tribal Development Department
- 45. Urban Development Department
- 46. Youth Services and Sports Department

---

## SCHEDULE-B

### 1. AGRICULTURE DEPARTMENT

1. Administration of Agricultural Acts
2. Agricultural Production and Extension
3. Agricultural Training, Stipends and Scholarships
4. Plant Protection of Crops
5. Agricultural Loans and Advances
6. Seed Farms and Seed Certification
7. Soil Testing, Soil Survey and Land Use
8. Grow More Food Campaign
9. Agricultural Information Service
10. Intensive Agricultural Projects
11. Agricultural Implements and Allotment of Tractors
12. Himachal Pradesh University Agricultural Complex
13. Matters relating to small farmers/marginal farmers and agricultural labour
14. Reclamation of waste land for agriculture

15. Minor Irrigation
16. Agricultural Financing
17. Gram Sewak Training Centres
18. Establishment, budget and accounts matters
19. Soil Conservation on Agricultural Lands
20. Tea Development, Processing and Marketing
21. Coffee Cultivation and Development

## **2. ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT**

1. Administration of the Acts relating to the Department
2. Animal Husbandry Programme and extension work
3. Veterinary aids and services—Hospitals, Dispensaries outlying Dispensaries including Artificial Insemination Centres.
4. Schemes relating to the development of cattle, sheep and goats, horses, mules, poultry, piggery, etc.
5. Disease investigation Schemes
6. Dairy development and development of Gosadans and Goshalas
7. Key Village Schemes
8. Milk Supply Schemes
9. Training in Veterinary Science and Animal Husbandry
10. Establishment, budget and accounts matters
11. Administration of sections 35, 94 and 100 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 in relation to Himachal Pradesh State Co-operative Milk Producers Federation Ltd., Himachal Pradesh State Co-operative Wool Federation and their constituent co-operative institutions.

## **3. AYUSH DEPARTMENT**

1. Development of ISM Pharmacies/Central Assistance
2. Conference pertaining to Ayurvedic and Unani System of Medicines
3. Matters relating to Himachal Pradesh Ayurvedic College Paprola
4. Homeopathic, Ayurvedic and Unani Board Acts and Rules
5. Administration and running of Regional Ayurvedic Hospitals, District Ayurvedic Hospitals, Ayurvedic Unani and Homeopathic Dispensaries.
6. Participation in the National Health and Family Welfare Programme
7. All matters relating to Board of Ayurvedic and Unani System of Medicine, Himachal Pradesh Management and running of Ayurvedic Pharmacies and Research Centre.
8. Education and Training in Ayurvedic, Unani and Homeopathy System of Medicine
9. Establishment, Budget and Accounts

## **4. CO-OPERATION DEPARTMENT**

1. All work relating to Co-operative Societies of all types and at all levels, registered under the Co-operative Societies Act, except administration of section 35, 94 and 100 of the Himachal Pradesh State Co-operative Societies Act, 1968 in relation to Himachal Pradesh State Co-operative Milk Producers Federation Ltd., Himachal Pradesh State Co-operative Wool Federation and their constituent co-operative institutions.
2. Urban Co-operative Bank
3. Land Mortgage Bank
4. Grant of loans and subsidies to Societies



5. Investment in share capital of the Societies
6. Crop Loan Schemes
7. Marketing of Agricultural Produce
8. Distribution of fertilizers, seeds and other agricultural inputs through the Co-operatives.
9. Co-operative processing and ware-house activities
10. Co-operative Law, Act and Rules
11. Audit of Co-operative Institutions
12. Consumers Co-operative Stores
13. Liquidation, Arbitration and Execution of Awards
14. Special Schemes of medium and long term credits
15. Registration of Societies under Societies Registration Act, 1860
16. Establishment, budget and accounts matters

## **5. ELECTION DEPARTMENT**

1. Elections to the Parliament
2. Elections to State Legislative Assembly
3. References from and to Election Commission
4. Establishment, budget and accounts matters

## **6. ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT**

1. Elementary Education i.e. Education from Class-I to VIII
2. Teachers Training and Training Institutions upto Elementary Level
3. Grant-in-aid for Elementary Educational Institutions
4. Scholarships for Elementary Education
5. Text Books
6. Sports in Elementary Education
7. Establishment, budget and accounts matters relating to Elementary Education
8. Linguistic Minorities and allied matters, relating to Elementary Education
9. All other matters/Programmes/activities relating to Elementary Education
10. Adult Education Scheme/Literacy Scheme (Non formal Education)
11. State Council of Educational Research and Training
12. School Library
13. Nursery Schools

## **7. ENVIRONMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT**

### **(A) Environment and Pollution Control:**

(a) To exercise all the powers vested under all Act and Rules pertaining to protection of environment and control of pollution. Implementation/ enforcement of all environment legislation on behalf of the State Government, which cannot be implemented by State Board, or any other agency:

1. Water [Prevention and Control of Pollution] Act, 1974
2. Water [Prevention and Control of Pollution] Cess Act, 1977
3. Air [Prevention and Control of Pollution] Act, 1981
4. Environment [Protection] Act, 1986 (Rules listed below)
5. Bio-medical Waste [Management and Handling] Rules, 1998

6. Hazardous Waste [Management and Handling] Rules, 1989
  7. Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989
  8. Rules for manufacture, use, import and storage of Hazardous Micro-organisms, genetically Engineered Micro-organism or Cells, 1989.
  9. The Recycled Plastic Manufacture and Usage Rules, 1999
  10. The Ozone Depleting Substances [Regulation and Control] Rules, 2000
  11. The Batteries [Management and Handling] Rules, 2001
  12. The Noise Pollution [Regulation and Control] Rules, 2000
  13. The Municipal Solid Wastes [Management and Handling] Rules, 2000
  14. Nodal Agency for Environmental Clearance
- (b) Other functions under environment and pollution control are as under:
1. Collection, preparation and dissemination of-"Environmental Inventory" on the State Resources in particular and on the Himalayan Region in general.
  2. To deal with all matters pertaining to environmental awareness among the masses, trainings, and research on the environment and pollution control.
  3. Monitoring and assessment of impact of development of projects on environment
  4. Dovetailing of the environmental concerns in the development processes through Environmental Planning to ensure environmentally compatible land use and ecosystem specific conservation and sustainable use of all resources.
  5. Research and Development on the environment protection and pollution control independently as well as in collaboration with premier institutions in the field of environment.
  6. Inventorisation of sources of hazardous chemicals and waste, creation of database on the treatment technologies and providing consultancy for the concerned.
  7. To study the likely impacts of agricultural and horticultural activities and study of "Non-Point Sources of Pollution" such as chemical fertilizers, pesticides, insecticides and other chemicals on soil and water resources, flora, fauna and communities in the State and to suggest mitigation measures/alternatives in this regard
  8. To advise the Government on the Environmental issues
  9. To examine the cases of Environment Impact Assessment and recommend the same to the Government of India.
  10. Complete control of SEIA and MC, SEIAA and SEAC under EIA mechanism
  11. To consider the validity and facts contained in the Environmental Impact Assessment and monitoring of Environment Management Plan prepared by the Project Proponents.
  12. Monitoring of implementation of Environmental Safeguards as specified by the Government of India at the time of Environmental Clearance to the various projects proponents in the State.
  13. Monitoring of Pollution Control measures/devices adopted by the various industries/proponents.
  14. All matters pertaining to Natural and man-made disasters and to suggests mitigation/remedial action plan programmes.
  15. To create data bank on disaster management related to potential industrial accidents and mitigation through instruments such as Onsite and Offsite Emergency Plan and Public Liability Insurance cover etc.
  16. To make coordination among the various agencies of the State Government, such as H.P. State Environment Protection and Pollution Control Board which are involved in environment protection and pollution control.
  17. To deal with all matters relating to Bio-diversity, Biosphere, Mitigation and Management of Natural Disasters, Protection and Conservation of the Wetlands, Grass-lands etc.

18. To deal with all environmental education programmes awareness programmes and to promote pro-active disclosure of environment monitoring and management information by the project proponents and the regulators.
19. To deal with all matters relating to the environmental litigation with respect to aforesaid rules and regulation and Acts.
20. Formulation/ maintenance of environmental standards in respect of various pollutants in the State.
21. Natural Disaster and Climate Change
22. Matters relating to Environmental Planning

**(B) Science and Technology:**

1. To develop/ modify/adapt new technologies in any area relevant to the State of Himachal Pradesh.
2. To disseminate and propagate new technologies for improvement of scientific intervention in developmental needs of the State.
3. To create new databases with the use of modern technologies
4. To develop appropriate technologies for use in the State of Himachal Pradesh
5. Propagation of use of Space Technology to develop models for optimum use of resources that promote alternative sustainable mode of development.
6. To enhance scientific and technical capacity and infra-structure in the State
7. To develop effective liaison with national and international scientific institutions
8. To evolve Science and Technology Policy for the State
9. To address issues like—Organic Pollution, Research and Development, Clean Technologies, Carrying Capacity Studies, Life Cycles, Sustainable Development, Biodiversity and Genetic Engineering.
10. To direct efforts towards evolving and establishing industrial and technological linkages.
11. Establishing efficient state-wide system of scientific and technological information
12. To promote the role and importance of science and technology in socio-economic development.
13. Promoting relevance of science towards society and enhancing gender equality in participation of S&T input.
14. Promote consultation, linkages and networking among S&T institutions including Universities, Industry, Research and Development, NGO and the Government Sector.
15. Undertake capacity building programmes to promote emerging technologies under science popularisation programme.

**(C) Bio-Technology:**

1. Formulation and implementation of Bio- Technology Policy in the State
2. Strengthening of Human Resource and existing infrastructure in Bio-Technology and its continuous improvement for generating skilled manpower in Bio-Technology and Technological upgradation of R&D Institutes and Universities within the State.
3. Promotion of Bio-Technology and Bioinformatics based activities for entrepreneurship development and employment generation in the State with emphasis on industries based on local bio-resource including forest/animal genetic resource and tissue culture.
4. Generation of resources from Government of India and International donors for promoting emerging technologies in Bio-Technology.
5. Establishment of Bio-Technology incubation facilities in private/public/joint sectors
6. Setting up of Bio-Technology Parks and Bio-Technology Industrial Clusters at various locations in the State.

7. Diversification of farming through introduction of superior and disease free improved genotypes, development of protocols and their refinement for commercial production (including medicinal and aromatic herbs, orchids and other ornamental plants).
8. To attract small entrepreneurs and other industrial houses for making investments in Bio-Technology based ventures in the State.
9. Development of marketing network for products based on Bio-Technology at national as well as international level.
10. Establishment of Joint Venture Companies (JVCs) with private investors/other organizations with an integrated approach from laboratory to industry and market.
11. Creation of Venture Capital Fund for promotion of Bio-Technology based business.
12. Setting up of facility for organic certification in the State
13. Implementation of Rules for manufacture, use, import, export and storage of hazardous micro-organisms, genetically engineered, organisms, cells or crops.

## **8. DEPARTMENT OF STATE TAXES AND EXCISE**

1. Administration of Excise and Taxation Acts and the rules made thereunder
2. Taxes on sale or purchase of goods
3. Taxes on luxuries including taxes on entertainment, amusements betting and gambling
4. Taxes on professions, trades and callings
5. Taxes on urban immovable properties
6. Additional Goods Tax
7. Tolls tax
8. Agriculture Produce Tax- Matters relating to
9. Intoxicating Liquors, Narcotic Drugs and Opium
10. Excise Duties on alcoholic liquors for human consumption and toilet preparations
11. Prohibition policy
12. Establishment, budget and accounts matters

## **9. FINANCE DEPARTMENT**

### **(a) Finance**

1. Preparation and compilation of State Budget
2. Supplementary Estimates and the Excess Demands for Grants and Appropriations
3. Prescribing of Units of appropriation
4. Management of Public funds including :
  - (a) Investment of surplus cash balances
  - (b) Contingency Fund
  - (c) Watching progress of receipt
  - (d) Recovery of Government of India's share in Plan Expenditure and resources for Plan Expenditure.
  - (e) Assessment of recoveries of Plan Expenditure
5. Financial scrutiny of new items of expenditure
6. Budget Control of expenditure
7. Taxation proposals
8. General financial administration including:
  - (a) Authority to decide the extent to which the audit of receipts and stores, stock accounts should be enforced;
  - (b) Framing of rules, regulating the conditions of service of Government employees including revision and relaxation thereof;
  - (c) State's share of Income-Tax;

- (d) State's share of Union Excise Duties
  - (e) State's share of Estate Duty; and
  - (f) Grant in lieu of the State's share of taxes on Railways fares
9. Tendering of advice on matters affecting directly the finances of the State that is to say:
    - (a) Grants, contributions, supplies and services, contingencies, recoveries from payments to other Government Departments etc., State loans and advances and cases relating to money matters generally defalcations, embezzlements and losses occurring in grants made for contingencies and "Supplies and Services".
    - (b) Emoluments, pensions, gratuity and allowances including travelling Allowance of officers and establishment.
    - (c) Loans and Advances such as car advances, house building advances, passage advances and G.P. Fund advances etc.
    - (d) Defalcations, embezzlements and losses occurring in treasuries
  10. Advice cases involving financial implications etc. relating to all Departments
  11. Borrowing by the State Government from the market and giving guarantees on the loans raised by Statutory Autonomous Bodies.
  12. Framing of Financial Rules and Delegation of Financial Powers
  13. Examination of proposals for the increase or decrease in the rates of the existing taxes and tapping of additional resources.
  14. Foreign exchange
  15. Control of Treasuries and Sub-Treasuries
  16. Economy measures, saving schemes
  17. Personal Ledger Accounts
  18. State Lotteries
  19. Audit Reports — Accountant General and Examiner, Local Funds Accounts
  20. Public Accounts Committee and Estimate Committee Reports
  21. Revision of Scales of pay including fixation of pay
  22. Supervision over income and expenditure of the State
  23. Disposal of Audit Objections
  24. All matters relating to Banks and Banking Commission
  25. Pension cases of the employees of erstwhile States.
  26. State Insurance
  27. Contingency paid staff and telephones
  28. H.P. State Finance Commission
  29. All policy matters relating to formulation/ amendment in the existing policy of providing employment assistance to the dependents of the deceased Government servants including issue of instructions as and when required and providing of employment assistance to the eligible dependents thereunder.

**(b) Himachal Pradesh State Audit Department**

1. Audit of the Accounts of—
  - (a) Municipal Corporations/ Committees including Notified Area Committees
  - (c) Gram Panchayats, Block Samitis and Zila Parishads
  - (d) Court of Wards
  - (f) Personal Ledger Accounts
  - (g) Guardian and Ward Account
  - (h) Universities
  - (i) Receipt and funds of educational institutes such as Pupil Fund, Sports Fund, Red Cross Fund, Tournaments Funds, Science Fund including Industrial Schools.
  - (j) Ferries, Hospitals, Veterinary Dispensaries, Grants-in-aid, Taxes etc.

- (k) Charitable Endowments and Trusts.
- (l) Miscellaneous accounts at the instance of Finance Secretary
- 2. Preparation of Annual Report of the working of L.A.D.
- 3. Establishment, budget and accounts matters

**(c) Treasuries, Accounts and Lotteries**

- 1. Treasuries
- 2. Sub-Treasuries
- 3. Payments of Bills, Pensions and Accounting for Government receipts
- 4. Procurement and distribution of judicial and non-judicial stamps
- 5. Treasury Manual
- 6. Establishment, budget and accounts matters
- 7. All matters relating to Lotteries

## **10. FISHERIES DEPARTMENT**

- 1. Administration of Fisheries Acts
- 2. Development of Fisheries and Marketing
- 3. Establishment, budget and accounts matters

## **11. FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT**

- 1. Essential Commodities, Acts, Orders and Rules made thereunder
- 2. Essential, controlled, partially controlled and other commodities like sugar, salt, kerosene, cement etc.—Procurement, control and distribution thereof.
- 3. Foodgrains and their products—Procurement and distribution including administration of connected legal orders.
- 4. Rice and Flour Mills
- 5. Government Foodgrains Godowns
- 6. Fair Price Shops
- 7. Brick-kilns
- 8. Establishment, budget and accounts matters
- 9. Weights and Measures
- 10. Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission

## **12. FOREST DEPARTMENT**

- 1. Administration of Forests Acts
- 2. Deployment of I.F.S. personnel excepting appointment of C.C.F. and officers of equivalent rank.
- 3. All matters relating to forest, Government as well as private including forest settlements, afforestation working plans, forest contracts, preservation, grant of rights etc.
- 4. Exploitation of forests produce major and minor including timber and resin.
- 5. Land reclamation, preservation and water shed management.
- 6. Mechanized logging schemes
- 7. Resin and turpentine factories
- 8. Construction of roads, buildings, bridges and water canals in forests essential for the better management of forests.
- 9. Management, preservation and conservation of wild life
- 10. Dhaula Dhar Project
- 11. Establishment, budget and accounts matters
- 12. Soil conservation on forest lands and other waste land
- 13. Eco-tourism

**13. GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT****(a) General, Political and Miscellaneous**

1. Annual Administration Report—Instructions regarding
2. Channel of correspondence between the Government of India, State Governments and abroad.
3. Death of High Dignitaries — Action to be taken on
4. Discretionary grants – Matters relating to
5. Move of Offices
6. National Anthem
7. National Integration
8. National Security Rules
9. Praman and Prashansa Patras
10. Portraits of National Leaders
11. Classification and re-classification of offices
12. Re-organization of District Administration
13. Security arrangements in offices
14. Central and State Citizen Councils
15. Accommodation including accommodation in the Secretariat, office and Residential accommodation for Deputy Commissioners and other Officers and all pooled residential accommodations.
16. Estate Office and allotment of Government accommodation
17. Governor's Secretariat
18. Governor's Address to Vidhan Sabha
19. Matters relating to and arising out of Statehood
20. Matters relating to boundary disputes
21. Problems arising out of the Re-organization of Punjab in 1966 including integration and allocation of services and division of assets and liabilities.
22. Development of Inter-State Border Areas – Matters relating to.
23. All matters relating to International Boarder including development of International Boarder Districts.
24. Indo-Tibetan Trade
25. Northern Zonal Council Business
26. Governor's Conference Business
27. Administrative Officers Conference
28. Merger of enclaves with Himachal Pradesh
29. Demands from various organizations including political parties
30. Secretariat staff and departmental cars
31. Parliament Questions, Assembly Questions (Affecting more than one department).
32. Matters relating to Political Sufferers
33. Post-war Services Reconstruction Fund
34. Rulers, their properties and privy purses
35. Fortnightly Reports to the Government of India
36. Postal, Telegraphs, Telephones and Wireless facilities in Himachal Pradesh
37. Matters affecting more than one Department
38. Administration of Himachal Pradesh Benevolent Fund
39. Declaration of Gazetted and Local Holidays
40. Independence Day, Republic Day, Himachal Day, Martyr's Day, U.N.O. Day and other Religious days—Celebration of.
41. Census
42. Miscellaneous work

43. Circuit houses and reservation of accommodation in such circuit houses and rest houses as from time to time by the Government.
44. Re-organization of Districts and Tehsils etc.
45. Rationalization of Committees at State/ District level – Instructions thereof
46. District Relief Fund, Chief Minister's Relief Fund and other funds—Collection of and other allied matters.
47. Honours and distinctions
48. H.P. Rajput Kalyan Board and H.P. Brahmin Kalyan Board

**(b) Confidential and Cabinet**

1. Secret matters
2. Meetings of the Cabinet and its Sub-Committees
3. Allocation Rules and Rules of Business
4. Ministers, Chief Parliamentary Secretary, Deputy Ministers, Parliamentary Secretary—All question relating to.

**(c) Hospitality and Protocol**

1. Hospitality
2. Protocol Matters
3. State Guest
4. Establishment budget and accounts matters

**14. HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**

1. Medical and Public Health Acts and Rules
2. Formation and establishment of Himachal Pradesh Health Services Cadre
3. Deployment of Central Health Services Cadre personnel excepting appointment of Director of Health Services and officers of equivalent rank.
4. All matters relating to Himachal Pradesh Medical College including deployment of personnel.
5. Medical Attendance Rules
6. Public Health including sanitation
7. Family Planning, Maternity and Child Welfare-All references relating to
8. Education and Training in Public Health and Family Welfare and Medicine
9. Medical and Public Health Administration including Hospitals, Dispensaries, Allopathic and Health Centres, etc.
10. Drug Act and Rules made thereunder
11. Control of Epidemics, Leprosy, T.B.V.D, Malaria, Small-pox and other such diseases
12. Vaccination
13. Registration of births and deaths
14. Vital Statistics
15. Adulteration of food stuffs and other articles
16. Assistance from UNICEF and other international agencies for Medical and Public Health Programmes.
17. Admission of mental patients in Mental Hospitals
18. Supply of Medical items from Medical Stores Depots for Institutions under various Departments.
19. Establishment, budget and accounts matters
20. Implementation of Employees State Insurance Scheme



**15. HIGHER EDUCATION DEPARTMENT**

1. School Education
2. College Education
3. Himachal Pradesh University
4. Teachers Training and Training Institutions
5. Audio Visual Education
6. Sanskrit and Hindi Institutions
7. Social Education
8. Grant-in-aid for High and Higher Institutions
9. NCC and ACC
10. Scholarships and loans for general technical and professional education
11. Vocational guidance and counselling in Schools and Colleges
12. Community Centres and Vigyan Mandirs
13. Libraries
14. Text Books
15. Sports in Educational Institutions
16. Physical Culture and Education
17. Establishment, budget and accounts matters
18. Linguistic Minorities and allied matters relating thereto
19. Correspondence relating to Navodaya Vidyalayas
20. Correspondence relating to Central Schools
21. Correspondence relating to H.P. Board of School Education

**16. HOME DEPARTMENT**

1. Law and order
2. Passports and Visas
3. Foreign Missions

**(a) Home**

4. Foreigners Registration etc.
5. Resettlement of Pakistani Refugees
6. Arms and Ammunitions
7. Home Guards and Civil Defence
8. Appeals, Representations and petitions addressed to the President of India, Prime Minister of India and the Governor from members of Police Department.
9. Emergency Relief Organization
10. Police including Himachal Armed Police:
  - (a) Police Administration
  - (b) Arms and Ammunitions
  - (c) Appeals, Representations of the Police
  - (d) Security, intelligence, espionage and counter-espionage
  - (e) Border Security Force
  - (f) Cases Affecting Law and Order
  - (g) Advisory Committee under Preventive Detention Act
11. Appeals and mercy petitions, reformation, etc., of prisoners
12. Remissions and Paroles
13. Fortnightly Reports
14. Emergency measures
15. Armed Forces

16. Filing of Appeals against the orders of acquittals passed by Lower Courts/ High Court of Himachal Pradesh and applications in the court of competent jurisdiction for enhancement of sentences.
17. Withdrawal of prosecution cases pending trial from the courts of competent jurisdiction
18. Cypher Code
19. Extradition of offenders
20. Inner line restrictions
21. Nominal rolls of Missionaries
22. Purchase of property of foreigners
23. Press control including censorship, control and forfeiture of objectionable literature and prosecution.
24. Collection of information from various departments order passed by judicial courts against public servants.
25. Issue of permits for plying vehicles on restricted/sealed roads of Shimla Town
26. Implementation and administration of the H.P. Cinema (Regulation) Act, 1975
27. Establishment of Jails
28. Prisoners—Maintenance, transfer and release
29. Reformatory Schools
30. Administration, Discipline and running of the Industrial Units of the Jails Department.
31. Judicial lock-ups
32. Establishment, budget and accounts matters relating to Jails
33. Indian Police Service
34. Himachal Police Service
35. Land Acquisition for Defence purposes
36. Union/State War Book
37. Institution of Honorary Magistrates
38. Making a request to the High Court of Himachal Pradesh for issue of instructions to Courts expediting the disposal of cases etc.
39. Administration of Criminal and Civil Justice including Constitution powers, maintenance and organisation of Courts of Criminal and Civil Jurisdiction within the State.
40. Advocate General's Office-All references relating to, including preparation of High Court State Council List, establishment and budget matters.
41. Appointment of Special Judges under Criminal Law Amendment Act, 1952 for the trial of corruption cases.
42. All references relating to establishment and budget matters etc. of the High Court and Courts subordinate to it.
43. Delegation of powers to the Judicial Magistrates for the trial of cases under suppression of Immoral Traffic Act, 1956 and Rules framed thereunder.
44. Higher Judicial Service
45. Judicial Service
46. Conferment of Judicial powers
47. Constitution and organisations of the High Court
48. Appointment, resignation, etc. of the Chief Justice and Judges of High Court, their salaries, rights in respect of leave of absence, pension and allowances.
49. Judicial and Executive Functions-Separation of
50. Appointments, postings, transfers, leave etc. of the Government pleaders, public prosecutors, special public prosecutors and District Attorneys, Additional District Attorneys.

51. Defence or institution of criminal cases on proceedings filed against or by the State Government in Supreme Court, entertainment of summons issued by the Supreme Court in these cases.
52. Monitoring of all criminal cases and proceedings filed against or by the Government in the Supreme Court.
53. All matters relating to the establishment and budget of the Directorate of Prosecution

**(b) Vigilance and Anti Corruption**

1. All matters relating to eradication of corruption
2. Assistance to all departments in the processing of departmental enquiries
3. Vigilance Commission and Vigilance Committee
4. Vigilance and Anti-Corruption Bureau and Anti-Corruption Units
5. Reports and Returns of Vigilance work
6. Commission of Enquiry Act, 1952
7. Establishment, budget and accounts matters
8. All matters relating to the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 as amended from time to time.

**(c) Directorate of Forensics Services**

1. Forensic education, development and extension services & IEC
2. Enforcement and administration of acts relating to forensics
3. Analysis of cases referred by investigation agencies of the State and Central Government other departments and institutions of the State like courts, commissions etc. and other statutory and constitutional bodies.
4. Examination of scene of crime (location, collection, preservation of clues in-situ) and reconstruction of scene of crime.
5. To defend reports given in cases in the court of law other legal, judicial/quasi-judicial authorities.
6. Quality control analysis in cases referred by the Government departments/ institutions of the State and Central Government.
7. To advise the government of Forensic issues, provide inputs for security features in logos and in Government documents.
8. Evaluation of forensics reports as referenced/interpreted by the courts of law and other judicial and quasi-judicial authorities.
9. Capacity Building of officers from judiciary, administrations, police, prosecution etc. and dissemination of forensic knowledge and public interface.
10. Supporting the Himachal Pradesh Forensic Science Development Board for all its functions including implementation of Government of India's policies on forensics and human resources development.
11. Organization and participation in various promotional activities like national, international conferences, seminars, workshops, colloquium meetings etc.
12. Publication of journal, periodicals and research papers etc. connected with forensic
13. Preparation of annual administrative report and directory of the State FSL
14. Formation and establishment of Himachal Pradesh Forensic Services Cadre
15. Effective liaison with national and international scientific institutions, universities and work in collaboration on forensic projects, research projects in building up the capabilities of the department.
16. Liaison with other Government departments/ institutions etc., Directorate of Forensic Services and other allied bodies of Government of India and Directorate of Forensic Services of other States.

17. Forensics-in-disaster
18. Forensic policy for the State
19. Establishment, budget and accounts matters
20. To lay down rules and mechanism for the organization and working of State Forensic Science Laboratory, Regional Forensic Science Laboratories and different specialties established therein including new specialties like Digital Forensic, Voice Analysis etc., and District Mobile Forensic Units and State Finger Print Bureau with its set up in the State and about issuance of forensic reports/results.

### **17. HORTICULTURE DEPARTMENT**

1. Horticulture Development and Extension
2. Plant Protection of Horticultural Crops
3. Progeny orchards and Nurseries –including their registration and supervision
4. Fruit Development Board
5. Agro-Industries Corporation
6. Fruit and Vegetable Preservation, Cold Storages, Warehouses and other units
7. Horticultural Stipends and Scholarships
8. Horticultural Loans and Advances
9. Floricultural and Ornamental Gardening
10. Bee-keeping
11. World Bank Project on Horticulture
12. Training in Horticulture
13. Establishment, budget and accounts matters
14. Cultivation of Herbs by farmers and development of medicinal aromatic plants

### **18. HOUSING DEPARTMENT**

1. Schemes to be undertaken by the Housing Board
2. All other housing schemes, such as subsidized Industrial Housing Scheme, Village Housing Project Schemes and the Rural House Sites for Landless persons.

### **19. INDUSTRIES DEPARTMENT**

1. Progress of industrial Development in all the sectors excluding industrial co-operative and including—
  - (a) Sericulture—Central Silk Board
  - (b) Khadi and Village Industries –Khadi and Village Industries Commission
  - (c) Handloom—All India Handloom Board.
  - (d) Handicrafts—All India Handicrafts Board
  - (e) Small Scale Industries
  - (f) Medium and Large Scale Industries
  - (g) Marketing and Emporia
  - (h) Industrial Estates
  - (i) Industrial Survey
  - (j) Rural Industrial Project
  - (k) Industrial and financial assistance to industries
  - (l) Government owned industrial concerns except those under Forest Department
2. Registration of Firms
3. Geology
4. Mining

5. Grant of Loans and Subsidies for Industrial Enterprises
6. Mines, Minerals, Financial and Industrial Corporations
7. Trade and Commerce within the State and production, supply and distribution of manufactured goods and products of large scale and small scale industries.
8. Establishment, budget and accounts matters
9. Baddi Barotiwala Nalagarh Development Authority and allied matters thereto
10. Integrated Development of logistic sector

## **20. INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT**

1. Press, newspapers and periodicals
2. Publication and publicity including State Broadcasts
3. Exposition of the Governmental Policies
4. Advertisements
5. Publication of State Journals
6. Community Listening Schemes
7. Establishment, budget and accounts matters
8. Song and Drama Scheme
9. Information Centre Scheme
10. Exhibition Scheme
11. Mobile Cinema Scheme
12. Film Production Scheme
13. All matters relating to film policy, opening of theatre etc.

## **21. INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT**

1. Formulation and implementation of the Information Technology Policy in the State
2. Introduction of automation and cybernation control systems so as to ensure faster information processing within Government, including projects and activities relating to e-governance.
3. Promotion of investment in Information Technology Sector (hardware, software and services—particularly ITEs and BPO) and related activities and creation and upgradation of Information Technology infrastructure in the State.
4. Assistance in development and implementation of software packages for monitoring of key parameters and computerization of thrust areas in different departments and Semi Government organizations.
5. Creation of Government—Public Interface through unified service delivery channel by using Information Technology and Information Technology enabled infrastructure and also to launch awareness campaigns on the advantages of the use of Information Technology and related technologies in enhancing the standard of living and improving quality of life.
6. Standardisation of hardware/software platforms for the departments/organizations and to ensure dynamic monitoring of their prices and minimization of wasteful expenditure.
7. Administrative control of Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation.
8. Formulation of Strategy for a State wide Internet by minimizing
9. Development of Information Technology related communication infrastructure
10. Assistance to the Departments/Semi-Government Organizations in creating and updating websites.
11. Promotion of Information Technology Education and training in educational institutions and Government departments/Semi-Government Organizations and facilitation of development/dissemination of educational software and promoting programmes in Information Technology enabled education.

12. Organisation of various promotional activities like national/international conferences/seminars and participation in the same.
13. Follow up of Information Technology related projects/schemes posed to Government of India and its agencies and also other players in this field in India as well as abroad.
14. Facilitating establishment of Venture Capital Fund by financial institutions for growth of Information Technology industry in the State.
15. Identification of laws and rules which need to be modified or enacted to enable legal validation for transaction and also to develop specific Cyber-Coding for ensuring and maintaining secrecy and also to act as nodal agency/authority on behalf of the State Government for matters relating to Information Technology Act and similar other Central or State Legislations.
16. Maintenance of database for all Information Technology related material and human resources available in the State.

## **22. JAL SHAKTI VIBHAG**

1. Rural water supply schemes and drainage
2. Urban W.S.S. and drainage/sewerage and sanitation
3. Minor Irrigation
4. Major Irrigation
5. Medium Irrigation
6. Flood Control Works
7. Command Area Development/Check Dam Works
8. Integrated Multipurpose Projects involving major share of Irrigation Works
9. U.S. Aid Project works and allied bilateral foreign assisted projects
10. Acquisition of land required for the department and settlement of its claims
11. Arbitration Cases
12. Establishment, budget and accounts matters
13. Soil Conservation Works along roads and streams

## **23. LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT**

### **(a) Labour**

1. Implementation and administration of the following :—
  - (a) Factories Act, 1948
  - (b) Minimum Wages Act, 1948
  - (c) Payment of Wages Act, 1936
  - (d) Indian Trade Unions Act, 1926
  - (e) Motor Transport Workers Act, 1961
  - (f) Workman Compensation Act, 1923
  - (g) Indian Boilers Act, 1923
  - (h) Employees Provident Fund Act, 1952
  - (i) Working Journalists Act, 1955
  - (j) Industrial Disputes Act, 1947
  - (k) Employees State Insurance Act, 1948
  - (l) Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
  - (m) Payment of Bonus Act, 1965
  - (n) Employment of Children Act, 1938
  - (o) Maternity Benefit Act, 1961
  - (p) Plantation Labour Act, 1951
  - (q) Trade Employees Act, 1940

- (r) Industrial Establishments, National and Festival Holidays and Casual and Sick Leave Act, 1965.
  - (s) Shops and Commercial Establishment Act, 1958
  - (t) Other Acts passed by the State in respect of Labour Department
2. Labour Statistics
  3. Establishment, budget and accounts matters
  4. Man-power and Employment Scheme:—
    - (a) Employment Exchanges
    - (b) Extension of coverage of employment service
    - (c) Collection of employment market information
    - (d) Implementation of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959.
    - (e) Vocational Guidance and Employment Counselling
  5. Establishment, budget and accounts matter

#### **(b) EMPLOYMENT**

1. Apprenticeship training in designated trades under the Apprentices Act, 1961
2. Man-power and Employment Scheme:—
  - (a) Employment Exchanges
  - (b) Extension of coverage of employment service
  - (c) Collection of Employment market information
  - (d) Implementation of the Employment Exchanges(Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959.
  - (e) Vocational guidance and employment counselling
  - (f) Monitoring of employment generation and 70% employment to Himachalis
3. Establishment, budget and accounts matters

### **24. LANGUAGE, ARTS AND CULTURE DEPARTMENT**

1. All matters relating to Cultural Affairs
2. Grant-in-aid to Cultural Bodies
3. Language:—
  - (i) Language policy
  - (ii) Development of the State Language
  - (iii) Matters relating to adoption of Hindi as State Language
  - (iv) Language Teaching Scheme
  - (v) Establishment, budget and accounts matters of the Department
4. Museums, Archaeology, Archives
5. Temples, fairs and festivals etc.

### **25. LAW AND LEGAL REMEMBRANCER'S DEPARTMENT**

1. Advice on Legal Matters
2. Construction of Statutes, Acts, Regulations, Statutory Rules, Orders and Notifications.
3. Conveyancing and Drafting of Bills, Ordinances, Rules, Bye-laws, Notifications and Regulations.
4. Defence or Institution of suits or proceedings filed against or by the Government except criminal cases in Supreme Court.

5. Law Department Manual
6. Republication of Central Acts in the State Gazette including the work of their translation into Hindi/Pahari, if so desired by the Government of India.
7. Entertainment of summons issued by the Supreme Court/ High Court and other Subordinate Courts in Civil, Criminal or Writ cases against Government except Criminal Cases in Supreme Court.
8. Forwarding letters of probate and administration and letters of requests and interrogatories to the proper quarter for necessary action.
9. Indian Law Reports-Question connected with the printing, distribution, supply, audit etc.
10. Codification of Laws, Rules and Regulations.
11. Legal Remembrancer's office- All references relating to establishment and budget etc..
12. Official Receivers and Notaries Public- Appointment of.
13. State Law Reports and Legal Remembrancer's Library
14. Constitution of India- References relating thereto
15. To collect/compile and pursue the general observations of the Subordination Legislation Committee.
16. Translation of Acts, Ordinances, Bills and Statutory Rules, Orders, Bye-laws, Regulations into official language.
17. Authentication and publication of the authoritative Hindi versions of Acts originally enacted in English.
18. Authentication and publication of English text of Bills, Acts and Ordinances under article 348 (3) of the Constitution of India.

## **26. MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT**

1. Administration of Medical Education/Dental Education Acts and Rules
2. Formation and establishment of Medical Education Services/Dental Education Services Cadre.
3. All matters relating to H.P. Medical College/H.P. Government Dental College including deployment of personnel.
4. Matters relating to the Establishment and Management of Private Medical/ Dental/ Ayurveda and other allied Institutions in the State.
5. Education and training in Medical College and Dental College and Ayurvedic College.
6. Formulation of policy and programmes on Medical Education, Vocational Education relating to Medical/Dental/Ayurveda and para-medical disciplines in Medical and Dental and Ayurveda and training for the State of Himachal Pradesh in addition to the following:—
  - (a) Under-graduate and Post-graduate Medical/Dental Education including Ayurveda Education;
  - (b) Nursing Students Education upto B.Sc. level;
  - (c) B.Sc. technology;
  - (d) Laboratory Technicians/Radiographers etc. ;
  - (e) Operation Theater Assistants;
  - (f) Physiotherapy and occupational therapy and rehabilitative services ;
  - (g) Blood Transfusion Assistant;
  - (h) Hygienists and Mechanics(Dental);
  - (i) Refractionists and Ophthalmic Assistants;
  - (j) Training Courses being run in the various Institutions in the State Concerning with Medical/Dental/Ayurvedic disciplines.



7. Formulation of Recruitment and Promotion Rules for various Government Medical/Dental and Ayurvedic and Para-Medical Education Training Institutions in the State.
8. Formulation of policy for Vocational Education/Medical Education/Dental Education/ Ayurvedic Education outside the State.
9. Formulation of policy on human resource management for the assessment of :—
  - (a) Man-power needs of the various Medical/Dental/Ayurveda/Para-Medical Services required in the State, both in the Govt. and Private Sector;
  - (b) Organising Training Programmes/conferences both within the State and outside the State;
  - (c) Curriculum for pre-vocational education for various Para-Medical Courses being run in the State;
  - (d) Organising refresher courses for advanced Professional education for Medical/Dental/Ayurveda.
10. Liaison with the MCI/DCI and CCIM and other allied bodies of Government of India
11. Establishment/budget and accounts matters of Medical & Dental Institutions

## **27. MULTI-PURPOSE PROJECTS AND POWER DEPARTMENT**

1. Indian Electricity Act, 1910, Electricity (Supply) Act, 1948 and Indian Electricity Act, 2003- Administration and Enforcement.
2. Policy regarding Rural Electrification
3. Constitution and working of the Himachal Pradesh State Electricity Board
4. Tariff policy and Electricity duty
5. Establishment of Electrical Inspectorate and its administration and control
6. Inter-State meetings and Conferences on Power and Multipurpose Projects
7. Annual Administrative and Financial Reports of the H.P. State Electricity Board
8. Delegation of Powers to the Chairman, Himachal Pradesh State Electricity Board
9. Inter –State Water Disputes and Treaties/agreements on Power and Projects
10. Grant-in-aid/Loans to the Himachal Pradesh State Electricity Board and the execution of Guarantee needs.
11. Parliament/assembly Questions, Public Accounts Committee and Estimates/ Assurances Committee—Business relating thereof.
12. Budget Estimates and Annual Accounts of the Board—Laying thereof before the Legislative Assembly.
13. Liaison between the Government Department and the Board
14. Miscellaneous references regarding Electricity Board from the general public and the Government of India and other State Governments.
15. Claims/References under the Punjab Re-organisation Act, 1966.
16. Acquisition of Land for the H.P. State Electricity Board.
17. Constitution of various Committees/Councils of the Himachal Pradesh State Electricity Board.
18. The H.P. State Electricity Board Rules-Framing of
19. Policy cases—Issue of directions to the H.P. State Electricity Board
20. Cases relating to assets and liabilities amongst the Punjab State Electricity Board, Haryana State Electricity Board and the H.P. State Electricity Board.
21. Administrative Control of:—
  - (i) H.P. Power Corporation Limited
  - (ii) H.P. Power Transmission Corporation Limited, and
  - (iii) Directorate of Energy
22. Development of State/Private/Joint/Central Sector Hydro Electric Projects

**28. NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT**

1. To deal with the Policies, Plans, Acts and Rules related to ,—
  - (i) Solar Energy-including photovoltaic devices;
  - (ii) Improved chulhas and research and development thereof ;
  - (iii) Integrated Rural Energy Programme (IREP);
  - (iv) Geothermal Energy, Wind Energy ; and
  - (v) Other non-conventional/ renewable sources of energy.
2. Administrative control of HIMURJA (Himachal Pradesh Energy Development Agency).

**29. PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT**

1. Himachal Pradesh Panchayati Raj Act and Rules thereunder
2. Establishment and Constitution of Gram Panchayats, Panchayat Samities and Zila Parishads.
3. Re-organisation and bifurcation of Panchayats
4. Control, Inspection and supervision of Panchayati Raj Institutions
5. Scrutiny, approval of Budget and accounts and Expenditure of Panchayati Raj Bodies
6. Complaints and enquiries against the office bearers of the Panchayati Raj Bodies
7. Audit of Accounts of Panchayati Raj Bodies
8. Training Institutions for Training of Officers/Officials of Panchayati Raj and office bearers of Panchayati Raj Institutions.
9. Publication of Journals and other periodicals connected with Panchayati Raj
10. Budget, Accounts and Establishment matters of the Department
11. Grant-in-aid to Panchayati Raj Bodies
12. State Election Commission:—
  - (i) Elections to Panchayati Raj Institutions
  - (ii) Elections to Local Bodies
  - (iii) Elections to Gurdwaras

**30. PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT**

1. Assurances given by the Ministers on the Floor of the House-Policy and Co- ordination
2. References to and from Legislative Assembly
3. Prevention of disqualification of members of the Legislative Assembly and matters connected therewith.
4. Chief Whips/ Whips Conference.
5. Work relating to the Committees of the Legislature
6. Appointment of M.L.As. on the Committees and other bodies set up by the Government.

**31. PERSONNEL DEPARTMENT****(a) APPOINTMENT**

1. All India Services- General Matters relating to Personnel
2. Indian Administrative Services
3. Cases of Supersession of All India Service Officers
4. Himachal Administrative Service
5. Appointment of Heads of Departments
6. Deputy Secretaries and Under Secretaries other than cadre officers

7. Public Service Commission:—
  - (i) Functions and limitations thereof
  - (ii) Establishment, Budget, Accounts and other matters
8. All policy matters relating to recruitment and promotion except policy for providing employment assistance on compassionate grounds.
9. Services Rules of all Departments
10. Government Servants Punishment and Appeal Rules
11. Policy regarding service matters:—
  - (i) Verification of character and antecedents
  - (ii) Postings and transfers
  - (iii) Concessions
  - (iv) Marriages
  - (v) Casual Leave
  - (vi) Retirement
  - (vii) Confidential Reports
  - (viii) Date of birth (Changes)
  - (ix) Declaration of posts as Gazetted
  - (x) Departmental Examination
  - (xi) Deputation
  - (xii) Efficiency Bars
  - (xiii) Medical Certificates
  - (xiv) Memorials.
  - (xv) Re-employment
  - (xvi) Seniority and confirmation
12. Service Associations
13. Appointment of :—
  - (i) Chairman-*cum*-MD and Directors (if the officers are borne on the Cadre of IAS) and Executive Director (Personnel) (if requested by the Administrative Department) of Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd.
  - (ii) Managing Directors of the Corporations and the Himachal Pradesh Agricultural Marketing Board set up under an Act/ Statute.
  - (iii) Administrator of the Municipal Corporation.
  - (iv) Chairman and Members and Secretary of the Himachal Pradesh State Housing Board.
14. Directories and Year Book—revision of
15. Allocation of subjects between the Administrative Secretaries
16. Himachal Pradesh Staff Selection Commission-all matters concerning

#### **(b) SECRETARIAT ADMINISTRATION**

1. All matters relating to the appointment, promotion, posting and transfers, pay, leave, recruitment etc. of the establishment of Himachal Pradesh Secretariat upto and including the level of Section Officers.
2. Secretariat Library
3. Telephones in the Secretariat
4. House-keeping jobs of the Secretariat staff
5. Budget and accounts of Secretariat Administration

#### **(c) ADMINISTRATIVE REFORMS**

1. The Secretaries Committee on Administrative Reforms.
2. Undertaking programmes of planned reviews as a means of identifying areas where detailed studies are likely to prove significant and effective in bringing out improvements, efficiency and economy in administration.

3. Undertaking studies of organizations and method of working
4. Assessment of staff requirements under new schemes involving a large number of new posts.
5. Evolution of work norms
6. Devising schemes of delegation of financial and cognate powers for :—
  - (i) Administrative departments of the Government;
  - (ii) Executive Heads of departments; and
  - (iii) Field Officers below the executive heads
7. Organizing the preparation of departmental manuals, handbooks, standing orders, guard files, etc.
8. Designing appropriate forms for submission of different kinds of proposals
9. Undertaking inspections and test-checks to ensure observance of prescribed rules and procedures.

#### **(d) TRAINING**

1. All matters relating to Himachal Pradesh Institute of Public Administration including budget, accounts, establishment etc.
2. Conduct of training courses, Seminars, Refresher courses at the Institute of Public Administration and of Departmental Examinations in respect of services/ departments as may be assigned to the Himachal Pradesh Institute of Public Administration by the Government.
3. Revision of Rules, Manuals, Codes etc.
4. Research and Publications connected with the Public Administration
5. Consultative and Advisory Services in Management Techniques
6. All matters relating to deputation of officers for training abroad
7. Foreign visits of official delegations which include officers of the State Government, Public Sector Corporations and Government aided Boards.

#### **(e) ADMINISTRATIVE PLANNING AND EVALUATION**

1. Setting-up of Task Forces to identify areas in governmental sub-system where improvements in organizational structure and procedure can be made.
2. Review of control system so as to avoid delays at all levels and to reduce the number of occasions and purposes for which a citizen has to come into contract with Government.
3. To ensure that decision making processes throughout Government are decentralized means of appropriate delegations at all levels.
4. Introduction of performance appraisal so as to ensure accountable management and fixation of responsibility areas.

### **32. PLANNING DEPARTMENT**

#### **(a) PLANNING**

1. All matters relating to Plan Formulation including assessment of resources in consultation with the Finance Department laying down priorities, plan targets and earmarking of resources provided that in relation to matters affecting tribal areas and members of scheduled tribes, the Tribal Development Department shall be consulted.
2. Matter relating to plan co-ordination and periodic review of plan programmes provided that in relation to matters concerning Tribal Sub-Plan and Special Component Plan for scheduled castes, Tribal Development Department shall be consulted.
3. Evaluation of Plan Schemes and Programmes provided that in relation to Tribal Sub-Plan and the Special Component Plan for scheduled castes, Tribal Development Department shall be consulted.

4. Rationalization of ongoing Plan Schemes from time to time and introduction of new Plan Schemes.
5. Matter relating to co-ordination and liaison for all Externally Aided Projects
6. All matters relating to Centrally Sponsored Schemes and Central Sector Programmes wherein any counterpart State Funding is involved.
7. All matters relating to co-ordination and liaison with the Planning Commission and National Development Council.
8. All matters relating to State Planning Board
9. All matters relating to setting-up of District Level Planning Development and Twenty Point Programme Review Committees.
10. All matters relating to setting-up of Sub-Divisional Level Committees on Planning Development, Twenty Point Programmes Review and Redressal of Public Grievances.
11. All matters including policy on finalization of shelf of projects for funding under RIDF facility of NABARD.
12. Tendering advice to all departments on matters relating to Planning except for the Tribal Sub-Plan Areas.
13. Formulation, co-ordination and review of various decentralized Planning Programmes like Vikas Mein Jan Sahayog, Sectoral Decentralized Planning, Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana etc.
14. Co-ordination at the State Level on MP Local Area Development Scheme
15. All matters relating to Backward Area Sub-Plan
16. Matters relating to co-ordination of Manpower and Employment Planning.
17. Matters relating to co-ordination of economic aspects under Point 13 of 15 Point Programme for Minorities.
18. Matters relating to co-ordination of Agro-Climatic Regional Planning
19. Co-ordination of Implementation of Budget Assurances relating to various departments.
20. Matters relating to perspective Planning in various Sectors, Co-ordination and advice to various departments.
21. Co-ordination of Implementation of State Finance Commission Reports
22. Correspondence on priorities of MLAs and Coordination and Review thereof
23. Co-ordination of Credit Plans of various Banks

**(b) ECONOMICS AND STATISTICS**

1. State Income Computation thereof
2. Socio-Economic Surveys
3. Community development statistics and progress reports
4. Census of Employees
5. Official Statistics
6. Price Statistics
7. Labour Statistics
8. Factory Statistics
9. Statistical Training
10. Evaluation of Programmes.
11. Coordination of statistical work of various Departments
12. Village directories
13. Establishment, budget and accounts matters
14. District Good Governance Index (DGGI)

**(c) 20-POINT PROGRAMME**

1. Monitoring of 20-Point Programme
2. Evaluation of 20-Point Programme

**33. PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT**

1. Copy rights
2. Government printing work
3. Procurement and supply of stationery to the Government offices
4. Supply of Government Publications and Gazettes
5. Establishment, budget and accounts matters of the Department

**34. PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

1. Construction and maintenance of State buildings
2. Transfer of Government buildings from one department to another department
3. Acquisition of land for construction of roads and Government buildings and settlement of claims.
4. Construction of roads, bridges, ferries, tunnels, rope-ways, cause ways and other means of communications in the State.
5. Inland waterways
6. Toll Tax on bridges
7. Building and road boards
8. Establishment, budget and accounts matters
9. Matters relating to the buildings of Government of India in the occupation of Himachal Pradesh Government.

**35. REDRESSAL OF PUBLIC GRIEVANCES DEPARTMENT**

1. Laying down guidelines for setting -up of grievances redress machinery in all Ministries/Departments and providing information in this regard.
2. Ensuring the setting-up of a decentralized machinery for redress of grievances, monitoring its effective functioning, helping identify grievance-prone areas for systematic change and computerising the grievance handling operations.
3. Contacting the concerned officers to assist grievance redress
4. Laying down guidelines for formulating citizen's charter by Ministries/ Departments/ Organisations and States/UTs sharing information, co-ordinating activities for deployment of Charters.
5. Co-ordinating setting-up of Information and Facilitation Counters (IFC) in Ministries/ Departments.
6. Publicising the Grievance Redress Mechanism of Ministries/Departments and the various Citizen's Charters and IFCs.
7. Any other works allotted to it by Hon'ble Chief Minister
8. Representation from the public of Himachal Pradesh

**36. REVENUE DEPARTMENT****(a) LAND REVENUE**

1. Tehsildar's and Naib-Tehsildar's establishment
2. Land Revenue Establishment
3. District establishment under 19-General Administration
4. Departmental examination of Naib-Tehsildars, Tehsildars and Extra-Assistant Commissioner.
5. Settlement operations and its establishments
6. Revenue Appeals

7. Nautor Rules, Water Mills Rules, Grant of Proprietary Rights
8. Administration of Minor Canals Act and Rules
9. Land acquisition works including those of various projects and connected matters
10. Stamps
11. Recovery of Revenue
12. Loans and Subsidies
13. Policy matters relating to construction of New Townships, Sale of Plots, etc.
14. Courts of Wards
15. Miscellaneous cases including :—
  - (a) Nautor cases
  - (b) Transfer of Government lands
  - (c) Auction of land
  - (d) Encroachment cases
  - (e) Lambardari cases
  - (f) Rate of cesses
  - (g) Recovery of Government dues
  - (h) Writing off irrecoverable arrears
  - (i) Jagir and Maufi cases
  - (j) Suspension and remission of land revenue
  - (k) Assessment and annulment of land revenue
  - (l) Tenancy cases
  - (m) Business returns of Revenue Officers and Revenue Court cases
  - (n) Arable land utilization order
16. Establishment, Budget and Accounts matters

#### **(b) LAND RECORDS**

1. Registration and Registration Manual
2. Annual and Seasonal crop report
3. Agricultural Statistics
4. Weather statistics and reports
5. Revenue business and returns
6. Training and examinations of Kanungos and Patwaris
7. Land Records
8. Naib-Tehsildar examinations
9. Forecast report.
10. Crop-cutting experiments.
11. Agricultural wages
12. Farm harvest prices
13. Petition writers examination and training in registration of clerks and their examinations.
14. Training of "A" Class Naib-Tehsildars and Tehsildar candidates
15. Establishment, budget and accounts matters

#### **(c) DISTRICT GAZETTEER**

Preparation and revision of District Gazetteers

#### **(d) CONSOLIDATION OF HOLDINGS**

1. All matters relating to Consolidation of Holdings operations
2. Land Settlements
3. Establishment, budget and accounts matters

**(e) COLONISATION**

1. Colonisation of Government lands
2. Development of New Mandis and Factory areas, etc.

**(f) RELIEF, REHABILITATION AND DISASTER MANAGEMENT**

1. Administration, management, leasing out and allotment etc. of acquired evacuee property.
2. Disposal of surplus rural and urban evacuee properties transferred by the Government of India to the State Government by two package deals for disposal.
3. Relief and resettlement of uprooted persons, including grant of financial assistance
4. Recovery postponement, remission and write-off of various kinds of rural and urban loans and realization of other rehabilitation dues.
5. Resettlement of oustees of Major Projects
6. Establishment, budget and accounts matters
7. Administration of Wakf Property

**(g) LAND REFORMS**

1. Implementation of the land Reforms Laws
2. Agrarian Reforms Acts and connected matters
3. Inspection of the Offices of the Compensation Officers
4. Appointment of Compensation Officers under the Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act.
5. Appellate work
6. Establishment, budget and accounts matters

**(h) NATURAL CALAMITIES**

1. Relief to the sufferers of floods, famine and drought, fire, earthquake, avalanches, hail-storm etc.
2. Grant of gratuitous relief and loans to the sufferers
3. Suspension/Remission/Postponement of recovery of loans and other dues from the sufferers.
4. Co-ordination with other Departments with regard to the providing relief and assistance to the sufferers.
5. Rehabilitation of sufferers

**37. RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT**

1. Development Blocks
2. Integrated Rural Development Programme including TRYSEM and DWCRA
3. Expended IRD Programme
4. Jawahar Rozgar Yojna including Indira Awas Yojna, Million Wells Schemes, Special Innovative Projects.
5. Employment Assurance Scheme
6. Wasteland Development Projects
7. Micro Watershed Projects
8. Drought Prone Areas Programme
9. Desert Development Programme
10. Rural Sanitation Programme including State Scheme and Central Rural Sanitation Programme.



11. Gandhi Kuteer Yojna
12. Central Rural Housing Scheme
13. Supply of Improved Tools Kits to Rural Artisan
14. Integrated Handloom Village Development Scheme
15. National Programme on Improved Chullahs
16. State Institutions of Rural Development
17. Tailoring Centres
18. Social Education, Organisation of Mahila Mandals and Yuvak Mandals etc.
19. Renovation and remodelling of old Kuhls
20. Discretionary Grants by Ministers
21. Budget, Accounts and Establishment matters of the Department
22. Credit-cum-Subsidy Scheme sponsored by the Government of India including Low Income Group Housing Scheme and Middle Income Group Housing Scheme.

### **38. SAINIK WELFARE DEPARTMENT**

1. Liaison with Army
2. National Defence fund
3. Cantonments-Matters relating to
4. Sainik Welfare
5. L.S.S. Camps and Territorial Army
6. Selection of candidates from Himachal Pradesh for admission to Rashtriya Indian Military College, Dehradun.
7. Observance of Flag Day
8. Administration of Special Fund for rehabilitation of ex-servicemen
9. Administration of Himachal Pradesh Defence and Security Relief Fund
10. Administration of Chief Minister's Soldier's Amenity Fund
11. War Jagirs

### **39. SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT**

#### **(a) Scheduled Caste, Other Backward Classes and Minorities Affairs**

1. Removal of untouchability, beggary and other social disabilities
2. Probationary Services
3. Implementation of Welfare programme of,—
  - (a) Scheduled Caste
  - (b) Backward classes including notified communities
  - (c) Aged and infirm
  - (d) Persons with Disabilities
4. Voluntary Welfare Organisations-Field counseling and financial assistance.
5. Tibetan Refugees
6. Social Security Pensions
7. Social Security measures
8. Establishment, budget and accounts matters
9. Punjab, Jammu and Kashmir immigrants and allied matters
10. Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 with respect of Scheduled Castes.
11. P.C.R. Act, 1955
12. H.P. Beggary Prevention Act, 1979
13. The persons with Disabilities (Equal Opportunities Protection of Right and Full Participation) Act, 1995.

14. H.P. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979.
15. Welfare of Minorities
16. National Trust Act, 1999
17. Prevention of Drug Abuse
18. OBC Corporation/ Minorities Finance and Development Corporation/State OBC Commission.
19. Schedule Caste Sub-Plan
20. Follow up programme

**(b) Women and Child Development**

1. Programme related to welfare of Women and Children
2. Mukhya Mantri Kanyadan Yojna
3. Mukhya Mantri Bal Udhar Yojna
4. Mata Shabri Mahila Sashaktikaran Yojna
5. Integrated Child Development Scheme Service, (ICDS)
6. Integrated Child Protection Scheme, ICPS
7. Indira Gandhi Matritv Sahyog Yojna, ( IGMSY)
8. Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment Adolescent Girl-SABLA
9. Mother Teresa Matr Sambal Yojna
10. Beti Hai Anmol
11. Rehabilitation Scheme for Rape Victim and Sex workers
12. Separation of immoral trafficking in Women and Children
13. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
14. Juvenile Justice Act, 2006
15. Dowry Prohibition Act, 1961
16. Child Marriage Prevention Act, 2006
17. Gender Budgeting
18. Mahila Vikas Nigam
19. State Women Commission
20. H.P. Council for Child Welfare
21. Establishment, Budget and Accounts Matters
22. State home for women/ widow
23. Re-marriage and Self Employment for Women etc.
24. State Social Welfare Advisory Board
25. Voluntary Welfare Organizations-Field Counseling and Finance Assistance

**40. TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL  
TRAINING DEPARTMENT**

1. Technical Education
2. Training of Technical Manpower
3. Industrial Training Institutes
4. Craftsmen Training Scheme
5. Rural Industrial Training Institutes
6. Planning for Technical Manpower
7. Technical Education, Vocational and Industrial Training Department to function as Administrative Department for co-ordination of Skill Development Programme and Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam.

**41. TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT**

1. Development and promotion of Tourism

2. State and District Tourist Advisory Committees
3. Tourist Services- Supply of information, reservation of accommodation and provision of other amenities.
4. Hotel Legislation
5. Construction/ maintenance of departmental tourist accommodation
6. Sports such as Winter Sports, Golf, Boat Clubs, etc.
7. Recognition of Travel agents and Shikar agents
8. Matters relating to shooting of films in Himachal Pradesh
9. Establishment, budget and accounts matters
10. Fossil Park and Food Craft Institute
11. Development of lakes in Himachal Pradesh
12. Civil Aviation and Flying Clubs including Flying Training, Aero Sports Institute, Hang Gliding, Para Gliding Training and competitions, Site selection for airstrips, Helicopter services, Air-craft operations, upgrading of helipads and upgradation/ extension of airports.

#### **42. TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

1. All references relating to Establishment and budget matters etc. and offices subordinate to it.
2. Improvement Trust and Development Authorities

#### **43. TRANSPORT DEPARTMENT**

1. The Motor Vehicle Act, 1988 and Rules made thereunder
2. The Road Transport Corporation Act, 1950 and Rules made thereunder
3. Himachal Road Transport Corporation and all matters connected therewith
4. Himachal Pradesh Bus Stand Management and Development Authority Act, 1999 and all matters connected therewith.
5. Regulation of Motor Vehicles for Passengers and Goods Transport and all allied matters
6. State Transport Authority and Regional Transport Authorities
7. Water Transport and all matters allied thereto
8. Management and Development of road side bus/rain Shelters
9. The Himachal Pradesh Motor Vehicles (Taxation) Act, 1972- Administration thereof
10. All matters relating to intensification of Railway facilities in Himachal Pradesh
11. Passenger and Goods Tax Except Additional Goods Tax

#### **44. TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT**

1. All matters relating to planning generally e.g. assessment of resources, formulation of plans, laying down of targets and physical aspects and co-ordination in relation to matters affecting the tribal areas and the members of the Scheduled Tribes of the State.
2. Periodical assessment and evaluation of Plan activities in relation to matters affecting the tribal areas and the members of the Scheduled Tribes of the State.
3. All policy matters including introduction of new schemes affecting the tribal areas as well as matters relating to the members of the Scheduled Tribes consultation thereof by all administrative departments with the Tribal Development Department.
4. Initiation of any proposal concerning any other department in relation to matters affecting the tribal areas or the members of the Scheduled Tribes of the State after due consultations and agreements with the concerned departments.

5. Tendering advice to all departments in relation to matters affecting the Tribal areas and the members of the Scheduled tribes of the State.
6. Overall co-ordination and evaluation of all activities of any department in relation to the matter affecting the Tribal areas and the members of the Scheduled Tribes of the State.
7. Tribal Advisory Council
8. Integrated Tribal Development Projects
9. Establishment, budget and accounts matters of the Tribal Development Department
10. The Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968
11. Welfare of Scheduled Tribes
13. Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 with respect to Scheduled Tribes.
14. Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes including Single Line Administration.
15. All matters relating to Border Area Development Programme including policy

#### **45. URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**

1. Administration of the Act and Rules relating to Local Bodies
2. Budget and accounts of the Local Bodies
3. Taxation proposals of Local Bodies
4. Establishment of Local Bodies
5. Audit and Inspection Reports
6. Grant-in-aid and loans to the Local Bodies
7. Provision of civic amenities to the public and management of affairs of Local Bodies
8. Slum clearance and sewerage disposal schemes
9. Welfare schemes in Notified and Municipal Area
10. Seminars, conferences relating to Local Bodies
11. Training of Municipal Employees
12. Cattle trespass etc.
13. Establishment, budget and accounts matters
14. Urban Development
15. Ownership Rights for Slum Dwellers, Implementation of Slum Dwellers Programme and allied matters thereto.
16. Urban Estate Manali and Manu Market Manali

#### **46. YOUTH SERVICES AND SPORTS DEPARTMENT**

1. Formulation, implementation and co-ordination of programmes for Youth Service and Sports.
2. Involvement of Youth in development programmes and the 20-Point Programme.
3. Organisation of Youth and provision of infrastructural support for combating the problem of educated unemployed.
4. Matter relating to Sports Council
5. All matters relating to development and promotion of Sports
6. Mountaineering and Allied Sports Institute, Manali

**राजस्व विभाग  
(स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण)**

अधिसूचना

शिमला-2, 9 दिसम्बर, 2021

**संख्या: रैव स्टाम्प (एफ) 6-1/2020.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में 'यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या: रैव स्टाम्प (एफ) 6-1/2020 दिनांक 30-11-2021 में संशोधन करते हुए PM SVA Nidhi योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वैंडर, रेहड़ी वाला आदि के पक्ष में ऋण-विलेख की लिखित पर इस आदेश के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, स्टाम्प शुल्क प्रचलित न्यूनतम प्रभार रु0 100/- से घटाकर मात्र रु0 10/- प्रतिविलेख प्रभारित करने के आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
(**औंकार चन्द शर्मा**),  
प्रधान सचिव (राजस्व)।

*[Authoritative English text of this Government Notification No. Rev. Stamp (F) 6-1/2020, dated 09th December, 2021 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].*

**REVENUE DEPARTMENT  
(Stamp-Registration)**

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 09th December, 2021*

**No. Rev. Stamp (F) 6-1/2020.**—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899) as applicable in the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to reduce the Stamp Duty from minimum applicable rate of Rs. 100/- to Rs. 10/- (Rupees ten) to be charged on the instruments of hypothecation agreements for the loans sanctioned to the Street- Vendors, Rehriwala etc. under PM SVA Nidhi Scheme applicable in Urban Area.

By order,  
Sd/-  
(**ONKAR CHAND SHARMA**),  
*Principal Secretary(Revenue).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,  
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Usha Gupta d/o Sh. Dwarka Dass, V.P.O. Dulehar, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)

2. Om Prakash s/o Late Sh. Padam Nabh, r/o House No. 155, Ward No. 11, V.P.O. Purana Bazar, Tehsil Sundernagar, District Mandi (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

. . Respondent.

*Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1955.*

Usha Gupta d/o Sh. Dwarka Dass and Om Prakash Gupta s/o Late Sh. Padam Nabh applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1955 that they have solemnized their marriage on 30-07-1988 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-12-2021. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 23-11-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sundernagar, District Mandi (H.P.).*